

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर

गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र

31 मार्च ----- को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

भाग-एक नियुक्ति का विषय :

प्रतिवेदित अधिकारी प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक द्वारा भरा जाए

01. पूरा नाम -----
(महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नाम भी लिखें)
02. पिता का नाम -----
03. जन्मतिथि -----
04. शैक्षणिक अर्हता एवं वर्ष स्नातक----- एम.फिल.-----
स्नातकोत्तर----- पी.एच.डी.-----
05. वेतन व वेतनमान वेतन ----- वेतनमान-----
06. महाविद्यालयीन सेवा प्रारंभ करने की जानकारी -----
(अ) प्रथम नियुक्ति का पद, प्रकार एवं दिनांक -----
(ब) नियमित नियुक्ति का दिनांक -----
(स) वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक -----
07. वर्ष में किस-किस संस्था में पदस्थ रहे, अवधि का भी उल्लेख करें :
(यदि एक से अधिक संस्था में कार्य किया हो तो प्रत्येक संस्था की कार्य अवधि के लिए पृथक फार्म भरा जाये)
(i) -----
(ii) -----
(iii) -----

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा समीक्षा अन्तर्निहित किये गए कार्य की जानकारी

वर्ष के दौरान लिए गए पीरियड्स (कालखंड) की संख्या

आइ.ए.ए. का स्तर	संरक्षण की संख्या	कुल छात्र संख्या	व्याख्यान प्रायोगिक टिडोरियल विशेष कोचिंग
-----------------	-------------------	------------------	-------------------------------------------

1. स्नातक
2. स्नातकोत्तर

09. क्या उपस्थिति पंजी नियमित भरी गई -----
10. क्या उपस्थिति पंजी प्राचार्य को सौंपी गई -----
11. वर्ष के दौरान आपके द्वारा किये गए शोध कार्य का विवरण -----
12. प्रकाशित कार्य का विवरण -----
13. कितने छात्रों को शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन किये -----
 (अ) एम.फिल. के कितने छात्रों को -----
 (ब) पी.एच.डी. के कितने छात्रों को -----
14. कितने कमजोर छात्रों को विशेष कोचिंग दी -----
15. वर्ष में कितनी नई पुस्तकों का अध्ययन किया -----
 (पुस्तकों का नाम व लेखकों का नाम लिखें) -----
16. वर्ष के दौरान लिए गए अवकाश की प्रकृति एवं दिवस -----
17. शैक्षणोत्तर कार्यों का संक्षिप्त विवरण -----
 (अ) एन.सी.सी. -----
 (ब) एन.एस.एस. -----
 (स) परीक्षा संचालन -----
 (महाविद्यालयीन परीक्षा संचालन में क्या कार्य किया, कार्य की प्रकृति एवं कितने दिन इस कार्य का संचालन किया) -----
 (द) महाविद्यालय प्रशासन के लिए किये गए कार्य -----
 (जैसे अनुशासन, जाँच कार्य, छात्र संघ आदि) -----
 (इ) अन्य कार्य -----
 (जैसे - खेल संबंधी, सेमीनार आदि) -----

दिनांक

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक
के पूर्ण हस्ताक्षर

भाग - दो

(प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति)

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भाग-1 में दिये स्वमूल्यांकन पर टीप

01. क्या प्रतिवेदक अधिकारी के स्वमूल्यांकन में उल्लेखित किसी बिन्दु से आप असहमत हैं? यदि हाँ तो विवरण दें
02. महाविद्यालय उत्कृष्ट दायित्वों को समय पर पूर्ण करने में रुचि
03. क्या इन्होंने आबंटित कोर्स पूर्ण किया
04. छात्रों के लिये प्रयास
- (अ) देदिप्यमान छात्रों के लिये क्या प्रयास किये
- (ब) कमजोर छात्रों के लिये क्या प्रयास किये
05. उपरोक्त के क्या परिणाम रहे
06. प्राचार्य द्वारा सौंपे गये कार्यों में क्या तत्परता रही
07. निष्ठा
08. प्रतिवेदक अधिकारी का समग्र मूल्यांकन
- (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/साधारण/घटिया)
- टीप :- उत्कृष्ट या घटिया वर्गीकरण करने पर इसका

संकेतित करें।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी०वी०ए०एस०) हेतु
वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम	पदनाम
	विषय
	कर्मचारी कोड नं.
	
महाविद्यालय	

(भाग—क सामान्य सूचना)

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. विभाग :
4. जिस विषय में विशेषज्ञता हो
5. महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
 - i. प्रथम नियुक्ति का पद प्रकार एवं दिनांक
 - ii. नियमित नियुक्ति का दिनांक
 - iii. वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक
6. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड :
7. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
8. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
9. स्थायी पता (पिन कोड सहित) :

फोन नं. :

ई मेल :
10. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री/शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है :
11. अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनसे वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम/ ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण

12. वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

- (iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेपी शिक्षण-अनुशिक्षण पद्धतियों का उपयोग, विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	

- (iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक

न्यूनतम अंको की आवश्यकता - 75

- वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे/सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक/सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक-15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियाँ		

(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्योरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

III. (ग) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(i एवं ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रु. में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं / प्रस्ताव

क्र.सं.	नामांकन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रु. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिस्की डायग्नोसिस/पेटेंट का	API अंक

III. (घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी.एच.डी. या समान				

III. (ङ) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण-अनुशिक्षण-मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

(ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र. सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय है ?	API अंक

(IV) API अंको का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ			
II	सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I+II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्यौरा (जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शाये)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नत्थी करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो)

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारियाँ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नत्थी किए गए हैं ।

संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैंस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफॉर्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जाँच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी।

भाग-घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष

के स्व-मूल्यांकन पर टीप-

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत है ? यदि हाँ तो किन-किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
	बिन्दु-	कारण-
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशंसित अकादमिक निष्पादन सूचकांक (A.P.I.)	

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

संयुक्त संचालक
आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन
प्रकोष्ठ

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ0ग0)

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के अभिमत से सहमत हैं ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान -

दिनांक -

समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान -

दिनांक -

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र
31 मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये
ग्रंथपाल-संवर्ग

1. नाम
(महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नाम भी लिखें)
2. पिता/पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. शैक्षणिक योग्यता
5. वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति
का दिनांक तथा प्रकार
6. वेतनमान (अ) वर्तमान वेतनमान
- (ब) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान
पारित दिनांक
- (स) प्रवर श्रेणी वेतनमान
पारित दिनांक
7. सेवाकाल में पहले किस-किस
महाविद्यालय में पदांकित रहें
8. विचाराधीन वर्ष में पुस्तकालय बढ़ाने तथा
सुसज्जित करने में प्रमुख योगदान
(ग्रंथपाल उन्हें सौंपे गये कार्यों के निष्पादन
प्रतिपादन संलग्न करें)

प्रतिवेदित ग्रंथपाल के हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति

1. विचाराधीन वर्ष में पुस्तकालय बढ़ाने तथा
शुसाज्जित करने में कहा तक सफल रहे ।
2. उच्चाधिकारियों, सहकर्मियों तथा अधिनस्थों से संबंध
3. समय व्ययित्त
.....
4. कोई प्रतिकूल टीका/दंड दिया गया हो तो उल्लेख करें
5. निष्ठा
6. समय मूल्यांकन
उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया
(उत्कृष्ट या घटिया वर्गीकरण करने पर इसका
औचित्य भी स्पष्टतः अंकित करें)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

नाम तथा सील

दिनांक

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

तृतीय श्रेणी सहायकों/सहायक ग्रेड-दो (उच्च श्रेणी लिपिक) एवं अन्य लिपिक-
वर्गीय कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने का प्रपत्र

31 मार्च 20

को समाप्त होने वाली छः/ही/होने वाले वर्ष के लिये

1. नाम
2. धारित पद (मूल/स्थानापन्न/अस्थायी)
3. वेतन
4. गतवर्षों का संक्षिप्त विवरण
5. धर्मनिरपेक्ष एवं व्यवहार
6. आचरण/चरित्र
7. प्रारम्भ और टीप लिखने की योग्यता
8. कार्यालय प्रक्रिया और नियमों का ज्ञान तथा उनको प्रयोग करने की योग्यता
9. प्रकरण के परीक्षण की क्षमता
10. कार्य के निपटारों की तत्परता
11. अवस्थिति में नियमितता और समय की पारबंदी
12. उच्च अधिकारियों एवं सहयोगियों से संबंध
13. दैनिक कार्य जैसे अस्मिस्टेट की झायरी का रख-रखाव, गाड़ फाइलें, टिक्काडिंग आदि का ध्यान रखा जाना।
14. सविष्ठा
15. कर्मचारी द्वारा यदि कोई असाधारण या उल्लेखनीय कार्य किया गया हो तो यह संक्षेप में बतायें।
16. कार्य पर आभाव्य टिप्पणी
17. श्रेणीकरण (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/सौधारण अच्छा/घटिया) (उत्कृष्ट श्रेणी में सभी वर्गीकृत किया जाय जबकि संबंधित कर्मचारी में असाधारण गुण एवं कार्य प्रदर्शनात्मक स्तर देखा गया हो। ऐसा वर्गीकरण किये जाने का आधादा भी स्पष्ट रूप से बताया जाये)।

प्रतिवेदन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

टिप्पणी/आवश्यक निर्देश :-

निम्नलिखित के विशेष कार्य/उपलब्धि का भूखण्ड सामान्य टीप में किया जाये

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर

गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र

31 मार्च 20..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

क्रीड़ा अधिकारी संवर्ग

1. नाम
(महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नाम भी लिखें)
2. पिता/पति का नाम
3. जन्मतिथि
4. शैक्षणिक योग्यता
5. वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक तथा प्रकार
6. वेतनमान (अ) वर्तमान वेतनमान
- (ब) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान पारित दिनांक
- (स) प्रवर श्रेणी वेतनमान पारित दिनांक
7. वर्ष में किस-किस महाविद्यालय में पदस्थ रहे.
8. विचाराधीन वर्ष में खेलकूद आदि की व्यवस्था बढ़ाने में प्रमुख सहयोग / प्रयास
- (क्रीड़ा अधिकारी उन्हें सौंपे गये कार्यों के निष्पादन प्रतिवेदन संलग्न करें.)

प्रतिवेदित अधिकारी
क्रीड़ा अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम-

दिनांक-

प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति

1. विचाराधीन वर्ष में खेलकूद आदि की व्यवस्था बढ़ाने में प्रमुख सहयोग/प्रयास
2. उच्चाधिकारियों, सहकर्मियों तथा अधिनस्थों से संबंध
3. समग्र व्यक्तित्व
4. कोई प्रतिकूल टीका/दंड दिया गया हो तो उल्लेख करें
5. निष्ठा
6. सामान्य मूल्यांकन
- उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया
(उत्कृष्ट या घटिया वर्गीकरण करने पर इसका औचित्य भी स्पष्टतः करें)

दिनांक

प्राचार्य के हस्ताक्षर
नाम तथा सील

समीक्षक / स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी-संभागीय अतिरिक्त संचालक की टीप

अतिरिक्त संचालक के हस्ताक्षर

नाम-

दिनांक-

सील-

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/कुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) “समिति” से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
(घ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(ङ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
- (ड) दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,—
- (1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :—
 - (एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;
 - (दो) बेहतर आंख में परिषांधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या
 - (तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।
 - (2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्यास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनों कानों में सुनने का पूरा ह्यास हो।
 - (3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ों की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।
- (ढ) "नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

(ण) "सेट/स्लेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।

3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

- (घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे ।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।
7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।
8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

- (एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

- (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- (तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ज) सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप-(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं - अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है:

परन्तु -

(1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीस:- (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।

9. निरर्हता:- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि

यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

- (2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।
- (3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
- (4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अधधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा।
- (6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

- (3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (4) आयोग, उप-नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।
- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

- (9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
- (10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।
- (11) उप-नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।
13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:
- परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।
- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.— (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

- (दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रजिस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपयुक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

- (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।
- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

16. **आयोग से परामर्श.**— (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

- (2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. **आमेलन द्वारा भर्ती.**— (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-

- (एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;
- (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (चार) सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;
- (पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।

(2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :-

- (एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य-भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;
- (दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;
- (तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या दण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;
- (चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

- (पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रंथपाल या क्रीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हो, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए;
- (छः) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई है।
- (3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;
- (दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा है, इस नियम में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हो, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
- (4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

- (5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।
- (6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।
- (7) इस नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।
- (9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीडाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैंडर (डाइंग कैंडर) के रूप में बने रहेंगे, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
18. चयन सूची.— (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

- (2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।
- (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिबीक्षा.**— (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिबीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 (ख) परिबीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिबीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।
 (ग) परिबीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिबीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिबीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
 (2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
22. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य - स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह-प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राध्यापक (रू. 6000 से अधिक ए. जी.पी.)	-	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	-	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) ग्रंथपाल (रू. 8000 से अधिक ए.जी.पी.)	-	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000

अनुसूची-दो (नियम 6 देखिये)

स.क्र	सेवा / पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित)						
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	-	-	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	-	100%	-	राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के काडर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	187+6	-	100 %	-	25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	-	-	
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	-	100 %		ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। पदोन्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह-प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह-प्राध्यापक की पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्तें पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

6.	सह-प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	--	100 %	--	ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। सह-प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सहायक प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।
7.	सहायक प्राध्यापक	3855	100 %	--	--	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीड़ा अधिकारी	116	100 %	--	--	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%	--	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल डाइंग केडर के सहायक ग्रंथपाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीप:- अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पदों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रक्रिया, अनुसूची-चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

अनुसूची-तीन (नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	<p>(क)</p> <p>(एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हैं, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो।</p> <p>(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो, जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।</p> <p>(तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी-माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।</p> <p>(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ब. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सामेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।</p>
2.	सह: प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	<p>(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी. एच.डी. की उपाधि।</p> <p>(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो, जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो।</p> <p>(तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी-माध्ययुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।</p>

				(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी।
3.	सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	<p>(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक (अथवा/एवं 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।</p> <p>(ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा।</p> <p>(ग) उप-खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।</p> <p>(घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट/सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।</p>
4.	क्रीड़ा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	<p>(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल में श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।</p> <p>(ख) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो।</p> <p>(ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उद्देश्य से यूजी.सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यूजी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो।</p> <p>(घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।</p>
				(ङ) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

				<p>(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :-</p> <p>(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यक्षीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।</p> <p>(दो) उपरोक्त उप-खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगा: --</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">पुरुषों के लिए मापदण्ड</th> </tr> <tr> <th colspan="4">12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</th> </tr> <tr> <th>30 वर्ष तक</th> <th>40 वर्ष तक</th> <th>45 वर्ष तक</th> <th>50 वर्ष तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1800 मीटर</td> <td>1500 मीटर</td> <td>1200 मीटर</td> <td>800 मीटर</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">महिलाओं के लिए मापदण्ड</th> </tr> <tr> <th colspan="4">8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</th> </tr> <tr> <th>30 वर्ष तक</th> <th>40 वर्ष तक</th> <th>45 वर्ष तक</th> <th>50 वर्ष तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000 मीटर</td> <td>800 मीटर</td> <td>600 मीटर</td> <td>400 मीटर</td> </tr> </tbody> </table>	पुरुषों के लिए मापदण्ड				12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा				30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक	1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर	महिलाओं के लिए मापदण्ड				8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा				30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक	1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर
पुरुषों के लिए मापदण्ड																																				
12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा																																				
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक																																	
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर																																	
महिलाओं के लिए मापदण्ड																																				
8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा																																				
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक																																	
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर																																	
				<p>टीप:- कीडा अधिकारी के पद के लिये-</p> <p>(एक) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेन्सी द्वारा लिया जायेगा।</p> <p>(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थी, चयन प्रक्रिया के लिये अपात्र होंगे।</p>																																
5.	ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष	<p>(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।</p> <p>टीप -</p> <p>(1) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रदान की जायेगी, 55 या 50 प्रतिशत अंक को पूर्णांकित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।</p>																																

- (2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।
- (3) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

टीप- सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ग्रंथपाल के लिये :-

- (1) वे अभ्यर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत हैं, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगी :

- (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;
- (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;
- (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों (जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो);
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;
- (ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/प्रति-कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

- (2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है: -

(एक) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट)- न्यूनतम 50%

- (3) यूजीसी की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:-

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाइंट)	समतुल्य प्रतिशत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24

				<p>(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5: की छूट प्रदान की जा सकेगी। पात्रता के लिए 55: अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5: की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी।</p> <p>(दो) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5: की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55: से 50: तक होगी।</p> <p>(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55: के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

टिप्पणी :-

- (1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।
- (2) अनुसूची-तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

स.क्र.	वर्ग	उच्चतर आयु सीमा	
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरुष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष
2.	पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	50 वर्ष	48 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष

- (3) प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्नति, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर होगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विचार नहीं हो सका।	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा -सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा-सदस्य	
2.	प्राध्यापक/पदोन्नत प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग-अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जायेगी। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी।	तदेव	
3.	सह-प्राध्यापक	पदोन्नत प्राध्यापक/उप संचालक	उन सह-प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :-	तदेव	

			(क) सह प्राध्यापक के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।		
4.	सहायक प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	उन सहायक प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने- (क) सहायक प्राध्यापक के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) वेतनमान 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (घ) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।	तद्वै	अनुभव एवं योग्यता, जो कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति सह-प्राध्यापक के पद में की जायेगी।

टिप्पणी :-

- (1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अतः उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात्, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नतियां नहीं होंगी।
- (2) सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होंगी :-
 - (क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु-- सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी को, 15600-39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :-
 - (एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह पी.एचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;
 - (दो) यदि वे पी.एचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफ्रेशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,
 - (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

- (ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु— ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :-
- (एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;
- (दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और
- (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।
- (3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| (एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक | — | संयोजक |
| (दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग | — | सदस्य |
| (तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट) | — | सदस्य |
| (चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद | — | सदस्य |

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेगी।

नोट :- ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

अनुसूची-पांच
(नियम 17 (1) देखिये)

आवेदन का प्रपत्र
(सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ा अधिकारी/ग्रंथपाल के पद हेतु)

फोटो
पासपोर्ट
साइज
(अनुप्रमाणित)

1. नाम तथा पता :
- विषय :
2. राज्य का नाम (जहाँ जन्म हुआ हो) :
3. जन्म तारीख (अकों में) :
- (शब्दों में) :
4. पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी को आयु वर्ष माह दिन.....
5. शैक्षणिक अर्हताएं :-

मंडल/विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) हायर सेकेण्डरी				
(ख) स्नातक				
(ग) स्नातकोत्तर				

प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।

6. यदि एम.फिल/पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :
7. यदि अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें :
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें :
9. अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक हो :

तारीख.....
स्थान.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

Atal Nagar, the 16th January 2019

NOTIFICATION

No.-F1-12/2013/38-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the Chhattisgarh Higher Education Department (Collegiate Branch, Gazetted) Recruitment and Conditions of Service, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted) Recruitment Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Appointing Authority**" in respect of services means the Government of Chhattisgarh;

(b) "**Commission**" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "**Committee**" means a selection committee or departmental promotion committee as specified in Schedule-IV;

(d) "**Examination**" means a competitive examination held under rule 11 of these rules;

(e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

- (g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/25/4/84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
- (h) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules;
- (i) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Articles 341 of the Constitution of India;
- (j) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Articles 342 of the Constitution of India;
- (k) "**Services**" means the Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted);
- (l) "**State**" means the State of Chhattisgarh;
- (m) "**Persons with Disability**" means,-
- (1) A person who is blind, if he suffers from one of the following conditions:-
 - (i) Total loss of vision;
 - (ii) Intensity of eye sight is not more than 6/60 or 20/200 (shellan) in the better eye with the corrective lens; or
 - (iii) The frontal angle of vision is limited to an angle of 20° or less.
 - (2) A person who is deaf, if he lacks sensation of hearing required for daily purpose, to the extent that he cannot hear or understand even amplified sound. Such person who suffer from loss of hearing in the better ear to the extent of more than 80 decibals (maximum loss) or who have lost the sense of hearing in both the ears shall be included in this category.
 - (3) Those persons will be deemed to be suffering from physical infirmity who have a physical defect or deformity which restricts the bones, muscles or joints in body to function normally.
- (n) "**NET**" means National Eligibility Test conducted by UGC/CSIR;

(o) "**SET/SLET**" means State Eligibility Test conducted by the State of Chhattisgarh or SET/SLET conducted by any State on or before 02.06.2002.

3. Scope and application. - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service.- The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scales of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

- (a) by direct recruitment, through selection (competitive examination and interview);
 - (b) by promotion of members of the service;
 - (c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf; and
 - (d) By absorption in accordance with the procedure prescribed in rule 17, after a college has been taken over by the Government.
- (2) The number of persons recruited under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

- (5) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.
7. **Appointment in service.** - After the commencement of these rules, all appointment to the service shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
- (I) **Age** - (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);
- (c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh

Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary

Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years before from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

- (e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely:-

- (i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

- (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of the enrolment;
- (iii) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);
- (iv) Ex-servicemen/Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (v) Ex-Servicemen invalidated out of service;
- (vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc;
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;
- (g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award,

Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

- (h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations /Boards;
- (i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years;
- (j) In any case the maximum age shall not exceed 45 years for admission in Government service for the recruitment of the post of Assistant Professor/ Librarian/Sports Officer irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above;
- (k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of

clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(II) Educational qualifications - The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-III.

Provided that -

(1) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission justifies the admission of the candidate to the examination/selection;

(2) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for the

examination/selection at the discretion of the Commission.

(III) Fees: - (A) The candidate must pay the fees as prescribed by the Commission.

(B) The candidate who have been required to appear before medical board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Commission to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his

medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.

(1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/interview, shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he shall be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. Direct recruitment through Selection (Competitive Examination /Interview).

(1) The selection for recruitment to

the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time. Commission, if deems fit, shall conduct joint examination for recruitment in the service or any other service with consultation of the Government.

(3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Comportment-wise. Subject to the said provisions, preference shall be given to widow and divorcee for appointment.

(6) In addition to above, the posts for person with disability/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

- (7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (8) In addition to above the candidates who may be women/person with disability/ ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compare with other candidates.
- (9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per the sub-rule (7) as the case may be.
- (10) In such cases, where experience of certain period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Government, after consultation with the Commission, may relax the condition of experience to the

candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of Candidates recommended by the Commission.- (1) The Commission shall prepare and forward to Government, a list arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as may be determine by the Commission and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, persons with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be for one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

- (4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) and (3) to the Government for further action regarding appointment. However, no appointment shall be made from waiting list without approval of the Commission.
- (5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (6) The inclusion of candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.
- (8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, shall recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) The Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list shall automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (9) and (10), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Appointment by promotion. - (1) There shall be a Committee consisting of the members mentioned in Scheduled-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the

instructions issued by the General Administrative Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules framed by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service as specified in column (4) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility for promotion-
The calculation of the period of qualifying service on the 1st day of January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the

feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/ promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Government servants in Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of 1 year.

(3) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servant or upto 25% of number of public servant included in the select list, which ever is more, shall consider the name of public

servant with requisite number for each cadre for the purpose of inclusion of his name.

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable for promotion.

15. Preparation of list of suitable candidate. - (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 13 and 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Consultation with the Commission - (1) The list prepared in accordance with rule 15 shall be sent to the Commission by the Government along with following documents :-

- (i) the record of all the persons included in the list.
- (ii) the records of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV, who are proposed for supersession as recommended in the list.
- (iii) the recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.
- (iv) the remarks of the Government on the recommendations of the Committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

17. Recruitment by Absorption.- (1) The absorption of Principals, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Librarians and Sports Officers of non-government colleges taken over by the Government shall be made on the recommendations made by the Screening Committee after examining every case. The Committee shall consist of the following members:-

- (i) Chairman, Public Service Commission or a member of the Commission, nominated by the Chairman;
- (ii) Principal Secretary/Secretary, Higher Education, Government of Chhattisgarh;
- (iii) Commissioner, Higher Education, Government of Chhattisgarh;
- (iv) Two Principals of Government Post Graduate Colleges shall be nominated by the Government;
- (v) At least one member from SC/ST categories to be nominated by the Government, in case no member from this category is available in (i) to (iv) above.

(2) The Screening Committee shall recommend the cases referred to it for absorption to appropriate posts on the following basis:-

- (i) All those persons, who were recruited as regular appointees in the non-government colleges taken over by the Government according to the provisions given in the college code of the concerning universities prior to the commencement of the Chhattisgarh Uchcha Shiksha Anudan Ayog;
- (ii) No such person, shall be absorbed who is recruited after the commencement of the Chhattisgarh Education Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1967 and Chhattisgarh Education Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, who does not fulfill the minimum requirements prescribed in the said rules, at the time of appointment;

- (iii) No person shall be absorbed if at any time in the past he or she was removed or dismissed from Government or any other service for proved misconduct and /or criminal offence;
- (iv) No person shall be absorbed in Government Service if he or she has attained the age of superannuation according to the Government rules in force at the time of absorption;
- (v) No person appointed as or holding the post of a Registrar, or a Librarian or a Sports Officer, in a non-government college taken over by the State Government, shall be absorbed in Government Service, unless, at the time of appointment, such person answers such minimum requirements or holds such qualifications as may be laid down by the State Government by an order in writing;
- (vi) No person shall be absorbed in Government Service whose appointment is not approved as a regular appointment by the Chhattisgarh Uchcha Shiksha Anudan Ayog presently the State or the university as the case may be.
- (3) (i) No person shall be absorbed in a higher post in Government Service from the post on which he/she was working prior to the take over of the college by the Government;
- (ii) For being absorbed as Principal of a Degree College, a person working as Principal of a college taken over by the

Government shall, in addition to the other conditions prescribed under this Rule have a minimum of 14 years teaching experience out of which 3 years teaching experience shall pertain to teaching post graduate classes and two years teaching experience as Professor. For absorption to the post of Principal of Post Graduate College, a further experience of two years of working as Principal of a Degree College shall be necessary.

(4) The Screening Committee, after taking into consideration, the relevant provisions of this rule shall make suitable recommendations to Government. After the recommendations of the Committee the absorption orders of the concerning persons will be issued by Government according to the recommendations of the Committee.

(5) A person absorbed to a particular post shall get his/her seniority from the date the college was taken over.

(6) No leave shall be permitted to be carried forward by a person working in a non-government college on his/her absorption in Government Service. However, if such a person pays the leave salary contribution in respect of the service rendered in a non-government college, he/she shall be permitted to carry forward the leave so earned subject to the restrictions and maximum limits prescribed in the Chhattisgarh Leave Rules.

(7) No person absorbed into Government Service under the provisions of this Rule shall by virtue of the fact that he/she was earlier confirmed in service by the non-government college claim as of right to be confirmed in Government Service. Confirmation

of such persons shall be done in accordance with the Government rules in force from time to time.

(8) The provisions of these rules shall be and shall always be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 1971.

(9) The Principal, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Librarian, Sports Officer of the non-government college, taken over by the Government whose appointments were approved as a regular appointment by the Chhattishgarh Uchcha Shiksha Anudan Ayog or the University as the case may be, but are rejected by the Screening Committee for their absorption in Government Service due to any reason, will continue on the post, they held on adhoc and temporary basis in dying cadre, but will not get any benefit of seniority, promotion, annual increments and revision of pay-scale in Government Service as such.

18. Select List.- (1) The Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the Committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any, in its opinion that is just and proper, will approve the list.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of the civil services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) The select list shall be ordinarily valid upto 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the service from the select list. - (i) Appointment of the officers included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list.

(ii) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Probation. - - (1) (a) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years.

21. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

23. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA KUMAR JAISWAL, Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 4 and 5)

S.No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commissioner, Higher Education	01	Class-I	37000 - 67000 + AGP 10000
2.	Principal, P.G. College, Additional Director, Higher Education	58+8	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000 + Special Pay 3000
3.	Principal, Degree College, Joint Director, Higher Education and State Liason Officer (N.S.S.)	187+6	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000 + Special Pay 2000
4.	Professor and Deputy Director, Higher education	592+6	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000
5.	Pramoted Professor	Number not defined	Class-I	37400 - 67000 + AGP 10000
6.	Associate Professor	Number not defined	Class-I	37400 - 67000 + AGP 9000
7.	(a) Assisstant Professor (b) Assisstant Professor (More than Rs 6000 AGP)	3855 -	Class-II Class-I	15600- 39100 + AGP 6000 15600- 39100 + AGP 7000 15600- 39100 + AGP 8000 37400- 67000 + AGP 9000
8.	(a) Sports Officer (b) Sports Officer (More than Rs 6000 AGP)	115 -	Class-II Class-I	15600- 39100 + AGP 6000 15600- 39100 + AGP 7000 15600- 39100 + AGP 8000 37400- 67000 + AGP 9000

9	(a) Librarian	125	Class-II	15600-	39100	+	AGP
	(b) Librarian (More than Rs 6000 AGP)		Class-I	6000			
				15600-	39100	+	AGP
				7000			
			15600-	39100	+	AGP	
			8000				
			37400-	67000	+	AGP	
			9000				

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S.No.	Name of service/ post	Total Number of Duty Posts	Percentage of Duty post to be filled			Remarks
			By direct recruitment (See Rule 6(1)(1))	By Promotion of substantive members of service (See Rule 6(1)(2))	By transfer /deputa tion of persons of other services (See Rule 6(1)(3))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted)						
1.	Commissioner, Higher Education	01	--	--	--	An Officer of Indian Administrative Service of Supertime Scale on deputation
2.	Principal P.G. College and Additional Director, Higher Education.	58+8	--	100%	--	State Liason Officer shall be from amongst the degree, Principal Cadre, having seven years experience of National Service Scheme
3.	Principal Degree College, Joint Director, Higher Education and State Liason Officer National Service Scheme.	187+6	--	100%	--	25% from Direct Recruitment Professor 75% from Promoted Professor
4.	Professor and Deputy Director, Higher education	592	100%	--	--	
5.	Promoted Professors.	Number not defined	--	100%	--	These posts will be filled up through Departmental Promotion Committee. There will be no definite number of such posts for the promoted professors and it will change according to the number of Associate Professors fulfilling the expected conditions of seniority and eligibility. The Associate Professor will be promoted according to the Schedule-IV, regarding the completion of the

						service period and satisfying eligibility conditions as per the service record mentioned therein.
6.	Associate Professor			100%	--	These posts will be filled up through Departmental Promotion Committee. There will be no definite number of such posts for Associate professors and it will change according to the number of Assistant Professors fulfilling the expected conditions of seniority and eligibility. The Assistant Professor will be promoted according to the Schedule-IV, regarding the completion of the service period and satisfying eligibility conditions as per the service record mentioned therein.
7.	Assistant Professor	3855	100%		--	By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well.
8.	Sports Officer	116	100%		--	By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well.
9.	Librarian	125	98%	2%	--	(1) By competitive examination. The successful candidates shall be interviewed as well. (2) Only for assistant librarian of dying cadre, these posts shall not be filled up by promotion in future after promotion of these officers

Note: The procedure for appointment in academic grade pay (AGP) Rs. 7000, 8000, and 9000 to the posts mentioned in Serial No. 7, 8 and 9 shall be according to the note given in Schedule-IV.

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S.No.	Name of the posts included in service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Professors and Deputy Director, Higher education	31 years	45 years	<p>(A)</p> <p>(i) An eminent scholar with Ph.D qualification in the concerned/allied/relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as book and/or research/policy papers related to the subject.</p> <p>(ii) A minimum of 10 years teaching experience in university/college, and/or experience in research at the University/National level institutions/industries, including experience of guiding candidates for research at doctoral level.</p> <p>(iii) Contribution to educational innovation, design of new curriculum and courses, and technology - mediated teaching learning process.</p> <p>(iv) A minimum consolidated API score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in the Notification issued separately by the Government.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(B) An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, to be substantiated by credentials.</p>
2.	Associate Professor	29 years	43 years	<p>(i) Ph.D degree in the concerned subject with a good academic record.</p> <p>(ii) A minimum of 8 years of experience of teaching in university/college and / or experience in research at the University/National level institutions/ Industries including experience of guiding candidates for research at the doctoral level. A minimum of 5 publications as books and /or Research / Policy papers related to the subject.</p> <p>(iii) Expansion of teaching and training mechanism with Educational Innovation, new syllabus subjects with Technology media.</p> <p>(iv) minimum consolidated API score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in the Notification issued separately by the Government.</p>
3.	Assistant Professor	21 years	30 years	<p>(A) Good academic record as defined with atleast 55% marks (or and grade B in a 7-point grading system) at the Master's Degree level in a relevant subject from an</p>

				<p>Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.</p> <p>(B) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.</p> <p>(C) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (A) and (B), candidates, who are, or have been awarded a Ph.D Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Colleges.</p> <p>(D) NET/SLET/SET shall also not be required for such Master's Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.</p>																
4.	Sports Officer	21 years	30 years	<p>(A) A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent degree or B grade in a 7- point scale wherever a grading system is followed) with a consistently good academic record.</p> <p>(B) Record of having represented the University /college at the inter-university/inter collegiate competitions or the State in national championships.</p> <p>(C) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.</p> <p>(D) Passed the physical fitness test conducted in accordance with these rules.</p> <p>(E) However, candidates who are or have been awarded Ph.D degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./ Ph.D Degree) Regulation, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for the recruitment and appointment of Sports Officer or equivalent post.</p> <p>(F) PHYSICAL FITNESS TEST NORMS</p> <p>(i) Subject to the above provisions, all candidates who are required to undertake the physical fitness test shall be required to produce a medical certificate certifying that he/she is medically fit before undertaking such tests.</p> <p>(ii) On production of such certificate in sub-clause (i) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the following norm given below:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">NORMS FOR MEN</th> </tr> <tr> <th colspan="4">12 MINUTES RUN/WALK TEST</th> </tr> <tr> <th>Up to 30 years</th> <th>Up to 40 years</th> <th>Up to 45 years</th> <th>Up to 50 years</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1800</td> <td>1500</td> <td>1200</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>	NORMS FOR MEN				12 MINUTES RUN/WALK TEST				Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years	1800	1500	1200	800
NORMS FOR MEN																				
12 MINUTES RUN/WALK TEST																				
Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years																	
1800	1500	1200	800																	

				metres	metres	metres	metres
				NORMS FOR WOMEN			
				8 MINUTES RUN/WALK TEST			
				Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years
				1000 metres	800 metres	600 metres	400 metres
				<p>Note:- For the post of Sports Officer -</p> <p>(i) Physical Fitness Test shall be taken by the department or agency approved by the Higher Education Department of the Government of Chhattisgarh for candidates who have qualified written examination and interview.</p> <p>(ii) Candidate, who have not qualified in the physical fitness test, shall not eligible for selection process.</p>			
5.	Librarian	21 years	30 years	<p>(1) A Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or an equivalent professional degree notified by UGC or the State Government) and a consistently good academic record with knowledge computerization of library.</p> <p>NOTE :-</p> <p>(1) A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Differently-abled (Physically and visually different-abled)/ OBC (non- creamy layer) rounding off of 55% or 50% shall not be accepted and grace marks given by the university shall also not be accepted.</p> <p>(2) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC or SLET/SET in Library Science.</p> <p>(3) However, candidates who are or have been awarded Ph.D degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./ Ph.D. Degree) Regulation, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for the recruitment and appointment of Librarian or equivalent post.</p> <p>NOTE:- For Assitant Professor/ Sports Officers/Librarian :-</p> <p>(1) Those candidates registered before 11 July 2009 for M.Phil./Ph.D for the post of Assistant Professor / Sports Officer / Librarian shall be governed by the then ordinance of / byelaws/regulations of the concerned institution providing degree. The candidates having Ph.D degree shall be exempted from the minimum eligibility conditions subject to the conditions as follow:</p>			

- (A) The candidate has obtained Ph.D degree on regular basis.
- (B) Ph.D thesis has been evaluated by two external examiners.
- (C) The candidate has published two research papers (out of which atleast one in refereed journal) from his Ph.D research work.
- (D) The candidate has presented two papers from his Ph.D research work in seminars / conferences.
- (E) The candidate has faced viva-voce.
- The aforementioned (A) to (E) should be certified by Vice Chancellor / Pro Vice Chancellor / Dean Faculty (Academic) / Dean Faculty (UTD).

- (2) **Good Academic Record means:**
 (i) Under Graduate- At least 50%
- (3) According to the UGC conversion table the percentage of marks shall be converted as follows:-

Grade	Grade Point	Percentage Equivalent
'O'	5.50-6.00	75-100
'A'	4.50-5.49	65-74
'B'	3.50-4.49	55-64
'C'	2.50-3.49	45-54
'D'	1.50-2.49	35-44
'E'	0.50-1.49	25-34
'F'	0.00-0.49	00-24

- (4)
- (i) A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe /Differently-abled (Physically and visually different-abled/OBC (Non-creamy-layer) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a "point scale" wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.
- (ii) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September, 1991.
- (iii) Relevant grade which is regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed by a recognized university shall also be considered eligible.

Annotation:-

(1) The restrictions of circular of the General Administrative Department no F 3-2/2002/1-3, Raipur, dated 16.09.2008 regarding the "Maximum age limit 45 years" including all types of relaxations shall not be applicable for the direct recruitment to the post of Professors and Associate Professors.

(2) The upper age limit for the post of Professor/ Deputy Directors and Associate Professor, Higher Education under column (5) of the schedule III shall be as follows :-

NO.	CATEGORY	UPPER AGE LIMIT	
		PROFESSOR	ASSOCIATE PROFESSOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Male (Unreserved)	45 years	43 years
2	Male (SC/ST/OBC/Persons with disabilities)	50 years	48 years
3	Female (Unreserved)	55 years	53 years
4	Female (SC/ST/OBC/ Persons with disabilities)	60 years	58 years
5	Widow/ Abandoned / Divorcee (Reserved/Unreserved Categories)	60 years	58 years

- (3) The upper age limits to the post of Professors and Associate Professors through direct recruitment shall not be more than 60 years and 58 years respectively after taking advantage of different types of relaxations as specified in these rules.
- (4) The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are Local resident of State of Chhattisgarh, as per instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE-IV

(See rule 14 and 15)

S.No.	Name of service or Post from which Promotion to be made	Name of service or Post to which Promotion is to be made	Minimum period of service experience for promotion	Name of the member of the Selection Committee/ Departmental Promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Principal Degree College, Joint Director and State Liason Officer, National Service Scheme	Principal, Post Graduate College and Additional Director, Higher Education	Promotion to the post of Principal, Post Graduate College, from among those Degree College Principals who are having at least two years of experience of the post of Principal, shall be made on the basis of combined seniority list of Principal degree college cadre. The promotion shall be on the basis of merit-cum-seniority. Provided that, the condition of experience shall not apply to persons whose names could not be considered at the time of earlier promotions despite having seniority.	(1) Chairman, Public Service Commission or any member nominated by him - Chairman (2) Principal Secretary/ Secretary, Higher Education - Member (3) Commissioner, Higher Education - Member	--
2.	Professor/Promoted Professor and Deputy Director Higher education	Principal Degree College, Joint Director, Higher Education and State Liasoning Officer, NSS	Promotion to the post of Degree College Principal shall be made from among professors having at least two years of experience as professor on the basis of merit-cum-seniority. The Departmental promotion committee shall prepare different seniority lists of Promoted Professors & Directly recruited professors, for promotion to the post of Principal respectively in the ratio in which they were in the beginning of the year of the meeting of the departmental promotion committee. There shall be 25 percent post of Professor of direct recruitment and 75 percent post of promoted Professor on the post ofdo.....	--

			Principal out of these lists. The seniority list of the promoted professors will be made on the basis of their seniority in the list of assistant professors. The seniority list of the direct recruited professors will be on the basis of the seniority as shown in the selection list issued by the public service commission.		
3.	Associate Professor	Professor/ Deputy Director	Those Associate professors shall have eligible for promotion to the post of professors with 37400-67000+AGP 10000 pay scale who - (a) Have completed three years service as associate professors (b) A minimum consolidated API score as stipulated in the (API) based Performance Based Appraisal system (PBAS), for which a separate notification shall be issued by the Government. (c) Their performance based appraisal report has been very good for the past five years.do.....	--
	Assistant Professor	Associate Professor	Those Assistant professors shall have eligible for promotion to the post of Associate professors with 37400-67000+AGP 9000 pay scale who - (a) Have completed eight years of service as Assistant professors (b) Have completed at least three years of service in the pay scale of 37400-67000+AGP 9000 (c) A minimum consolidated API score as stipulated in the (API) based Performance Based Appraisal system (PBAS), for which a separate notification shall be issued by the Government. (d) Their performance based appraisal report has been very good for the past five years.do.....	In the basis of experience and qualification mention in the column number (4) in Schedule-IV the promotion of Assistant Professors shall be made on the posts of Associate Professors.

Note :

- (1) The posts of Assistant Librarian belong to dying cadre and they are to be abolished. Hence, after the promotion of the persons working in these posts as above, there shall be no promotions to the post of librarians in future.
- (2) Assistant Professor/Sports officer and Librarian shall have to fulfill the following qualifications to get senior scale and selection grade scale.
 - (a) For Senior Scale - Assistant Prof./Librarian/Sports officer shall be placed in the senior grade pay of 7,000 in the scale of 15,600-39,100 if they have :-
 - (i) Completed 6 years of regular service, 4 years and 5 years of service in case he is Ph.D. or M.Phil. degree holder respectively;
 - (ii) Have participated in one orientation course if they are Ph.D. holders and for others one orientation course and one refresher course which are qualitatively in accordance with the standards fixed by the University Grants Commission;
 - (iii) His performance evaluation has been constantly Satisfactory.
 - (b) For placement in Selection Grade Scale - All Assistant Prof./Librarian/Sports officer working in senior pay scale shall have the eligibility of being placed in Selection Grade Scale if they have:-
 - (i) completed five years service period in senior scale, as Assistant Prof./ Librarian/Sports officer with at least 11 years and for those Ph.D. and M.Phil. degree holders who have completed 9/10 years respectively;
 - (ii) having participated in two refresher courses/Summer institutions each of 4 weeks after having been placed in senior scale or have been continuously involved in programmes which are qualitatively equivalent to the standards fixed by the University Grants Commission; and
 - (iii) their performance evaluation has been constantly good.
- (3) For placement in Senior and Selection Grade Scale there shall be consisting of the following members in the Screening Committee :-
 - (i) Commissioner, Higher Education or an additional Director nominated by him - Convener
 - (ii) Deputy Secretary, Chhattisgarh Government, Higher Education Department - Member.
 - (iii) Principal of Govt. Post Graduate College - Member (Nominated by the Commissioner Higher Education)
 - (iv) An academician, associated with higher Education- Member.

Screening Committee shall perform the screening in accordance with the instruction issued from time-to-time by the Government for the determination of fitness for being shortlisted

Note :- Directives issued from time-to-time for placement in senior and selection grade scale by the UGC and Government shall be applicable.

SCHEDULE - V

(See Rule 17(i))

**Proforma of Application
(For the post of Assistant Professor/Sports Officer/Librarian)**Passport
size photo
(Attested)

1. Name and Address :
- Subject :
2. Name of the State :
- (where born)
3. Date of Birth (In figures) :
- (In words) :
4. In the year of advertisement for the post, age as on 1st Januaryyear
.....month days
5. **Academic Qualification :-**

Board/University	Year	Division	Subject	Marks obtained/Maximum Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A) Higher Secondary				
(B) Graduation				
(C) Post Graduation				

For each attested marksheet is required.

6. If M.Phil. / PhD degree has been awarded.
mention the topic and furnish the certificate :
7. If the candidate belongs to SC/ST category,
Scheduled Caste's and Scheduled Tribe's name be mentioned.
Attach certificate of the competent authority :
8. If the candidate is already employed,
mention designation, name of the
Institution and, name of the department. :
9. Any other information the candidate may
like to furnish. :

Date

Place

.....
Signature of the candidate

Computer Literacy Program for Non-teaching staff

https://www.gpscc.in/events_details.aspx?eid=86



Raipur, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 493221, India
Lat 21.415206°
Long 81.669629°
05/08/21 03:02 PM



आंचलिक 15-08-2021

कॉलेज में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया

धरसीवा। समस्त शासकीय कार्य ऑनलाइन घर से कार्य संपन्न करने के आदेश जारी होते रहे हैं। इसके पालन में आई समस्याओं के निराकरण हेतु इस कार्यक्रम की उपयोगिता समझाई गई। शा.पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा में प्राचार्य डॉ. विनोद शर्मा के निर्देशन में कम्प्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन महाविद्यालय द्वारा किय गया।

कंप्यूटर प्रशिक्षण में जानी बारीकियां

धरसीवा (नईदुनिया न्यूज)। लाकडाउन के दौरान शासकीय कार्य आनलाइन व घर से कार्य करने में होने वाली कंप्यूटर संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा के प्राचार्य डा. विनोद शर्मा के निर्देशन में पांच से 14 अगस्त तक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में समस्त कार्यालयीन एवं तकनीकी स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम के सफल संचालन में डा. जी नाग भार्गवी, देवाशीष प्रधान, उमेश वर्मा एवं समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

धरसीवा कॉलेज में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

धरसीवा. वर्तमान कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान समस्त शासकीय कार्य ऑनलाइन घर से कार्य संपन्न करने के आदेश जारी होते रहे हैं। इसके पालन में आई समस्याओं के निराकरण के लिए इस कार्यक्रम की उपयोगिता समझी गई।

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा में प्राचार्य डॉ. विनोद शर्मा के निर्देशन में 5 अगस्त से 14 अगस्त तक कम्प्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता एवं आशवासन

प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। महाविद्यालय के समस्त कार्यालयीन एवं तकनीकी स्टाफने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. विनोद शर्मा ने कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रकोष्ठ को शुभकामनाएं दी एवं भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित करने के लिए निर्देश दिया एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आशवासन दिया। कार्यक्रम के संचालन में डॉ. जी नाग भार्गवी, देवाशीष प्रधान, उमेश वर्मा एवं समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।



PARKING FACILITY



CONTENTS

Subject	Rule	Page No.
<u>CHAPTER-I</u> <u>PRELIMINARY</u>		
Short title and commencement	1	1
Extent of application	2	1
Definitions	3	1
Government servants on temporary transfer or on foreign service	4	2
Transfer from services or posts governed by other Leave Rules	5	2
<u>CHAPTER-II</u> <u>GENERAL CONDITIONS</u>		
Right to leave	6	3
Regulation of claim to leave	7	3
Effect of dismissal, removal or resignation on leave at credit	8	3
Commutation of one kind of leave into another	9	4
Combination of different kinds of leave	10	4
Maximum period of absence from duty	11	4
Acceptance of service or employment while on leave	12	4
<u>CHAPTER-III</u> <u>GRANT OF AND RETURN FROM LEAVE</u>		
Application for leave	13	5
Leave account	14	5
Verification of title to leave	15	5
Leave not to be granted in certain circumstances	16	6
Grant of leave on Medical Certificate to Government servant	17	6
Leave to a Government Servant who is unlikely to be fit to return to duty	18	7
Commencement and termination of leave	19	8
Combination of holidays with leave	20	8
Intimation of Leave at credit	21	9
Recall to duty before expiry of leave	22	9
Return from leave	23	9
Absence after expiry of leave	24	10

Subject	Rule	Page No.
CHAPTER-IV <u>KINDS OF LEAVE DUE AND ADMISSIBLE</u>		
Earned leave for Government servant serving in Departments other than Vacation Department	25	10
Calulation of earned leave	26	12
Earned leave for persons serving in vaction department	27	12
Half pay leave	28	14
Commuted leave	29	15
Leave not due	30	16
Extra-ordinary leave	31	17
Leave to probationer, a person on probation and an apprentice	32	17
Leave preparatory to retirement	33	17
Leave beyond the date of retirement, compulsory retirement or quitting of service	34	18
Persons re-employed after retirement	35	18
Leave Salary	36	18
Drawal of leave salary	37	19
CHAPTER-V <u>SPECIAL KINDS OF LEAVE OTHER THAN STUDY LEAVE</u>		
Maternity leave	38	19
Paternity leave	38-A	20
Child Adoption Leave	38-B	20
Special disability leave for injury intentionally inflicted	39	21
Special disability leave for accidental injury	40	22
Power to grant special disability leave	40-A	22
Power to grant leave Other than special disability leave and study leave	41	22
CHAPTER-VI <u>STUDY LEAVE</u>		
Conditions for grant of study leave	42	23
Sanction of study leave	43	24
Maximum amount of study leave that may be granted at a time and during the entire service	44	25
Accounting of study leave and combination with leave of other kinds	45	25
Regulation of study leave extending beyond course of study	46	25
Admissibility of allowances in addition to leave salary	47	26
Grant of travelling allowances	48	26
Execution of bond	48	26
Resignation or retirement after study leave or non-completion of course of study	49	26
	50	26

Subject	Rule	Page No.
Leave salary during the study leave	51	27
Counting of study leave for promotion, pension, seniority, leave and increments	52	28
Application for study leave	53	28
CHAPTER-VII <u>MISCELLANEOUS</u>		
Interpretation	54	28
Repeal and saving	55	28
LISTS OF FORMS		
Forms	Form No.	Page No.
Application for leave or for extension of leave	1	29
Form of leave account	2	30
Medical certificate for Governments servants recommended leave or extension of leave or commutation of leave	3	32
Medical certificate of fitness to return to duty	4	33
Bond to be executed by a Governments servant in permanent employ, when proceeding on study leave	5	34
Bond to be executed by a Governments servant in permanent employ, when granted extension of study leave	6	35
Bond to be executed by a Governments servant not in permanent employ,when proceeding on study leave	7	36
Bond to be executed by a Government servant not in permanent employ,when granted extension of study leave	8	38

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules, namely:-

RULES **CHAPTER-I** **PRELIMINARY**

- 1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010.
(2) They shall come into force on the 1st day of October 2010.

- 2. Extent of application.-** Save, as otherwise provided in these rules, these rules shall apply to all Government servants who are in service on the date, of coming into force of these rules and who are appointed to the civil services and posts in connection with the affairs of the State, but shall not apply to: -
 - (a) persons in casual or daily rated or part time employment;
 - (b) persons paid from contingencies;
 - (c) persons employed on work-charged establishments;
 - (d) persons employed on contract except when the contract provides otherwise;
 - (e) persons in respect of whom special provisions have been made by or under the provision of the Constitution or any other law for the time being in force;
 - (f) persons serving under a State Government Department on deputation from the Central Government or any other source, for a limited duration;
 - (g) members of the All India Services.

- 3. Definitions. -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires.-
 - (a) "Completed year of service" or "one year's continuous service" means continuous service of specified duration under the State Government and includes the period spent on duty as well as on leave including extra-ordinary leave;
 - (b) "Date of retirement" or "date of his retirement" in relation to a Government servant means the after noon of the last day of the month in which the Government Servant attains the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service;

- (c) "Foreign service" means service in which a Government servant receives his pay with the sanction of Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of any State or the Consolidated Fund of a Union Territory;
 - (d) "Form" means a form appended to these rules;
 - (e) "Government servant in quasi-permanent employ" means a Government servant who may be declared or deemed to be as Quasi-permanent under the C.G. Government servants (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960;
 - (f) "Government servant in permanent employ" means a Government servant who holds substantively or provisionally substantively a permanent post or who holds a lien on a permanent post or who would have held a lien on permanent post had the lien not been suspended;
 - (g) "Vacation Department" means a department or part of a department to which regular vacations are allowed, during which Government servants serving in the department are permitted to be absent from duty.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in Fundamental Rules shall have the meanings respectively assigned to them in Fundamental Rules.

4. Government servants on temporary transfer or on foreign service.-

(1) Government servants to whom these rules apply shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to Central Government or any other State Government or Union territory or while on foreign service within India.

(2) In the case of Government servants on foreign service outside India (including service with U.N. agencies within or outside India) or on temporary transfer to the Armed Force of the Union, these rules shall apply only to the extent provided in the terms and conditions of foreign service or temporary transfer, as the case may be.

5. Transfer from services or posts governed by other Leave Rules.-

Unless it be otherwise provided in these rules, a permanent Government servant to whom these rules do not apply: -

(a) When transferred temporarily to a service or post to which these rules apply, shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer; and

(b) when appointed substantively to a permanent post to which these rules apply, shall become subject to these rules from the date of such appointment, in which case the leave at his credit under the rules previously applicable to him shall be carried forward subject to the maximum limits of accumulation as laid down in rule 25. The leave salary in respect of the leave carried forward shall be borne by the Department or the Government from which the Government servant proceeds on leave.

CHAPTER-II

GENERAL CONDITIONS

- 6. Right to leave.-** (1) Leave cannot be claimed as of right.
- (2) When the exigencies of public service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, but it shall not be open to that authority to alter the kind of leave due and applied for except at the written request of the Government servant.
- 7. Regulation of claim to leave.-** A Government servant's claim to leave is regulated by the rules in force at the time the leave is applied for and granted.
- 8. Effect of dismissal, removal or resignation on leave at credit.-** (1) Any claim to leave to the credit of a Government servant, who is dismissed or removed or who resigns from Government service, ceases from the date of such dismissal or removal or resignation.
- (2) Where a Government servant applies for another post under the State Government but outside his parent office or department and if such application is forwarded through proper channel and the applicant is required to resign his post before taking up the new one, such resignation shall not result in the lapse of the leave to his credit.
- (3) A Government servant, who is dismissed or removed from service and is reinstated on appeal or revision, shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal, as the case may be.
- (4) A Government servant, who having retired on compensation or invalid pension or gratuity, is re-employed and allowed to count his past service for pension, shall be entitled to count his former service towards leave.

9. Commutation of one kind of leave into another.- (1) At the request of a Government servant the authority which granted him leave may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him when leave was granted, no commutation can be done after the employee ceases to be in service. The Government servant cannot claim such commutation as a matter of right.

(2) The commutation of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted to the Government servant, that is to say, any amount paid to him in excess, shall be recovered or any arrears due to him shall be paid.

Note- Extraordinary leave granted on medical certificate or otherwise may be commuted retrospectively into leave not due subject to the provisions of rule 30.

10. Combination of different kinds of leave.- Except as otherwise provided in these rules, any kind of leave under these rules may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave.

Explanation- Casual leave or optional leave which are not recognized as leave under these rules, shall not be combined with any other kind of leave admissible under these rule

11. Maximum period of absence from duty.- No Government servant shall be granted leave of any kind of a continuous period exceeding five years. (AMENDMENT)

12. Acceptance of service or employment while on leave.- (1) A Government servant (other than a Government servant who has been permitted a limited private practice or who has been permitted to undertake casual literary work or service as an examiner or similar employment) while on leave, including leave preparatory to retirement shall not take up any service or employment elsewhere, including the setting up of a private professional practice as accountant, consultant or legal or medical practitioner without obtaining the previous sanction of-

- (a) The Governor, if the proposed service or employment lies elsewhere than in India; or
- (b) the authority empowered to appoint him, if the proposed service or employment lies in India.

- (2) No Government servant while on leave, other than leave preparatory to retirement, shall ordinarily be permitted to take up any other service or employment.
- (3) No Government servant while on leave preparatory to retirement shall be permitted to take up private employment. If, however, a Government servant on leave preparatory to retirement is permitted to take up employment with a Public Sector Undertaking or a body referred to in sub-rule (2) of rule 33 and in that event also salary payable for leave preparatory to retirement shall be the same as admissible under rule 36.
- (4) In case a Government servant who has proceeded on leave preparatory to retirement is required, before the date of retirement, for employment during such leave in any post under the State Government in or out side India, the unexpired portion of the leave from the date of rejoining shall be cancelled.

CHAPTER-III

GRANT OF AND RETURN FROM LEAVE

- 13. Application for leave.-** (1) An application for leave or for an extension of leave must be made to the authority competent to grant such leave or extension in Form-I.
(2) Applications for leave on grounds other than ill health should be made at least three weeks before such date. This limit would, however, be six weeks if the leave applied for is preparatory to retirement. The authority competent to grant leave may accept belated application at its discretion.
- 14. Leave account.-** The Head of Office shall maintain a leave account in Form 2 for each Government servant.
- 15. Verification of title to leave.-** (1) No leave shall be granted to a Government servant until a report regarding its admissibility has been obtained from the authority maintaining the leave account. The order sanctioning leave shall indicate the balance of earned leave/half pay leave at the credit of the Government servant.
(2) (a) Where there is sufficient reason to believe that the obtaining of admissibility report will be unduly delayed, the authority competent to grant leave may calculate, on the basis of available information, the amount of leave admissible to the Government servant and issue provisional sanction of leave for a period not exceeding sixty days.

(b) The grant of leave under this sub-rule shall be subject to verification by the authority maintaining the leave account and a modified sanction for the period may be issued, where necessary.

16. Leave not to be granted in certain circumstances.- Leave shall not be granted to a Government servant to whom a competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from Government service.

17. Grant of leave on Medical Certificate to Government servant.- (1) An application for leave on medical certificate, made by a Government servant, shall be accompanied by a medical certificate in Form 3 given by an Authorized Medical Attendant or a Registered Medical Practitioner, defining as clearly as possible the nature and probable duration of the illness. Such application shall be submitted, as far as possible, prior to or simultaneously with commencement of the period for which leave is applied:

Provided that, in exceptional circumstances where it is not reasonably practicable for the Government servant to submit an application within the aforementioned time limit, it may be submitted not later than seven days from the date of commencement of the period of leave applied for:

Provided further that, in exceptional circumstances, where the authority competent to sanction leave is satisfied that it was not reasonably practicable for the Government servant to submit the required medical certificate along with his application for leave, it may, at its discretion condone a delay of not more than seven days, counted from the date of commencement of the period of leave applied for, in the submission of medical certificate by such Government servant.

(2) A medical officer shall not recommend the grant of leave in any case in which there appears to be no reasonable prospect that the Government servant concerned will ever be fit to resume his duties, and in such case, the opinion that the Government servant is permanently unfit for Government service shall be recorded in the medical certificate.

(3) The authority competent to grant leave may, at its discretion, secure a second medical opinion by requesting a Government Medical Officer not below the rank of a Civil Surgeon, to have the applicant medically examined on the earliest possible date.

(4) It shall be the duty of the Government medical officer referred to in sub-rule (3) to express an opinion both as regards the facts of the illness and as regards the necessity for the amount of leave recommended and for that purpose he may either require the applicant to appear before himself or before a medical officer nominated by himself.

(5) The grant of a medical certificate under this rule does not in itself confer upon the Government servant concerned any right to leave, the medical certificate shall be forwarded to the authority competent to grant leave and orders of that authority awaited.

(6) The authority competent to grant leave may, at its discretion, waive the production of a medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding seven days at a time. Such leave shall not, however, be treated as leave on medical certificate and shall be debited against leave other than leave on medical grounds.

18. Leave to a Government Servant who is unlikely to be fit to return to duty.-(1) (a) When a medical authority has reported that there is no reasonable prospect that the Government servant will ever be fit to return to duty, leave shall not necessarily be refused to such Government servant.

(b) The leave may be granted if due, by the authority competent to grant leave on the following conditions: -

(i) if the medical authority is unable to say with certainty that the Government servant will never again be fit for service, leave not exceeding twelve months in all may be granted and such leave shall not be extended without further reference to a medical authority;

(ii) if a Government servant is declared by a medical authority to be completely and permanently incapacitated for further service, leave or an extension of leave, may be granted to him after the report of the medical authority has been received, provided the amount of leave as debited to the leave account together with any period of duty beyond the date of the report of the medical authority, does not exceed six months.

(2) A Government servant who is declared by a medical authority to be completely and permanently incapacitated for further service shall -

(a) if he is on duty, be invalidated from service from the date of relief of his duties, which should be arranged without delay on receipt of the report of the medical authority, if however, he is granted leave under sub-rule (1), he shall be invalidated from service on the expiry of such leave.

(b) if he is already on leave, be invalidated from service on the expiry of that leave or extension of leave, if any, granted to him under sub-rule (1).

19. Commencement and termination of leave.- Except as provided in rule 20, leave ordinarily begins on the day on which the transfer of charge is affected and ends on the day preceding that on which the charge is resumed.

20. Combination of holidays with leave.- (1) Except in cases, where for administrative reasons the leave sanctioning authority has specifically withheld the permission for prefixing and/or suffixing holiday(s) to leave, when the day, immediately preceding the day on which a Government servant's leave begins or immediately following day on which his leave expires is holiday or one of a series of holidays, the Government servant can leave his station at the close of the day before, or return to it on the day following, such holiday or series of holidays.

(2) In the case of leave on medical certificate-

(a) When a Government servant is certified medically unfit to attend office, holiday(s), if any, immediately preceding the day he is so certified shall be allowed automatically to be prefixed to leave and the holiday(s) if any, immediately succeeding the day he is so certified (including that day) shall be treated as part of the leave.

(b) When a Government servant is certified medically fit for joining duty, holiday(s) if any, succeeding the day he is so certified (including that day) shall automatically be allowed to be suffixed to the leave and holidays if any, preceding the day he is so certified shall be treated as the part of the leave.

(3) If holidays are prefixed to leave, the leave and any consequent re-arrangement of pay and allowances take effect from the day after the holidays.

(4) If holidays are suffixed to leave, the leave is treated as having terminated and any consequent re-arrangement of pay and allowances takes effect from the day on which the leave would have ended if holidays had not been suffixed.

21. Intimation of Leave at credit.- The order sanctioning earned leave/half pay leave to a Government servant shall indicate the balance of such leave at his credit.

22. Recall to duty before expiry of leave. - A Government servant while on leave, if recalled to duty before expiry of the leave, he shall be entitled: -

(a) If the leave from which he is recalled is in India, to be treated as on duty from the date on which he starts for the station to which he is ordered, and to draw: -

(i) travelling allowance under rules made in this behalf for the journey; and

(ii) leave salary, until he joins his post, at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty .

(b) If the leave from which he is recalled is out of India, to be treated as on duty from the date on which he starts for India, and to receive-

(i) leave salary, for the journey to India and for the period from the date of landing in India to the date proceeding to the date of joining his post, at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty;

(ii) a free passage to India;

(iii) refund of his passage from India, if he has not completed half the period of his leave by the date of leaving for India on recall, or three months, whichever is shorter;

(iv) travelling allowance, under the rules for the time being in force, for travel from the place of landing in India to the place of duty .

23. Return from leave.- (1) A Government servant on leave shall not return to duty before the expiry of the period of leave granted to him, unless he is permitted to do so by the authority which granted him leave.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (I), a Government servant on leave preparatory to retirement shall be precluded from returning to duty, save with the consent of the authority competent to appoint him to the post from which he proceeded on leave preparatory to retirement.
- (3) A Government servant who has taken leave on medical certificate may not return to duty until he has produced a medical certificate of fitness in Form 4.
- (4) (a) A Government servant returning from leave is not entitled, in the absence of specific orders to that effect, to resume as a matter of course the post which he held before going on leave.
(b) Such Government servant shall report his return to duty to the authority, which granted him leave or to the authority, if any, specified in the order granting him leave and await orders.

Note- A Government servant, who has been suffering from tuberculosis, may be allowed to resume duty on the basis of Fitness Certificate, which recommends light work for him.

- 24. Absence after expiry of leave.-** (1) Unless the authority competent to grant leave extends the leave, Government servant who remains absent after the end of leave, the period of such absence not covered by grant of leave shall have to be treated as 'dies-non' for all purpose including leave. He will not be entitled to any leave salary for the period of such absence and that period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave.
- (2) Willful absence from duty after the expiry of leave renders a Government servant liable to disciplinary action.

CHAPTER-IV

KINDS OF LEAVE DUE AND ADMISSIBLE

- 25. Earned leave for Government servant serving in Departments other than Vacation Department.-**
- (1)(a)(i) The leave account of every Government servant who is serving in a department other than a Vacation Department shall be credited with earned leave in advance in two installments of 15 days each on 1st January and 1st July every calendar year.

(ii) When a Government servant joins a new post without availing full joining time by reason that-

- (a) he is ordered to join the new post at a new place of posting without availing of full joining time to which he is entitled, or
- (b) he proceeds alone to the new place of posting and joins the post without availing full joining time and takes his family later within the permissible period of time for claiming travelling allowance for the family;

The number of days of joining time as admissible under sub-rule (4) of rule 5 of Chhattisgarh Civil Services (Joining Time) Rules, 1982, subject to the maximum of 15 days reduced by the number of days actually availed of, shall be credited to his leave account as earned leave:

Provided that the earned leave at his credit together with the unavailed joining time allowed to be so credited shall not exceed 300 days.

(b) The leave at the credit of a Government servant at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year, do not exceed the maximum limit of 300 days:

Provided that where the earned leave at the credit of Government servant as on the last day of December or June is 300 days or less but more than 285 days (excluding the unavailed portion of joining time credited to earned leave account during the previous half year), the advance credit of 15 days earned leave on first day of January or July to be accorded in the manner indicated under clause (b), shall instead of, being credited in leave account, be kept separately and first adjusted against the earned leave that the Government servant takes during that half year and the balance, if any, shall be credited to the leave account at the close of the half year, subject to the condition that balance of such earned leave plus leave already at credit do not exceed the maximum limit of 300 days.

(2) If a Government servant is on leave on the last day of any particular half of a calendar year, he shall be entitled to earned leave credited on the first of the succeeding half year, provided the authority competent to grant leave has reason to believe that the Government servant will return to duty on its expiry.

(3) The maximum earned leave that may be granted at a time to a Government servant shall be 180 days.

- 26. Calculation of earned leave.-** (1) Earned leave shall be credited to the leave account of a Government servant at the rate of 2-1/2 days for each completed calendar month of service, which he is likely to render in a half year of the calendar year in which he is appointed.
- (2) (a) The credit for the half-year in which a Government servant is due to retire or resigns from the service, shall be accorded only at the rate of 2-1/2 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation.
- (b) When a Government servant is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2-1/2 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.
- (3) If a Government servant has availed of extra-ordinary leave and/or some period of absence has been treated as 'dies-non' in a half year, the credit to be afforded to his leave account, at the commencement of the next half year shall be reduced by 1/10th of the period of such leave and/or dies-non, subject to a maximum of 15 days.
- (4) While according credit of earned leave, fractions of a day shall be rounded off to the nearest day i.e. fraction below half should be ignored and that of half or more should be reckoned as a day.
- 27. Earned leave for persons serving in vacation department.-** (1) (a) The leave account of a person serving in a vacation department shall be credited in advance with earned leave in two installments of five days each on the first day of January and July, of every year.
- (b) If a person serving in a vacation department has availed of extra ordinary leave and/or some period of absence has been treated as 'dies-non' during a half year, the credit to be accorded to his leave account at the commencement of the next half-year shall be reduced by 1/30th of the period of such leave and/or 'dies-non' subject to a maximum of five days.
- (c) The credit for the half-year in which a person working in a vacation department is appointed/ceases to be in service shall be allowed at the rate of 5/6 day for each completed month of service, which he has rendered in the half-year in which he is appointed or ceases to be in service.

- (2) Subject to provisions of sub-rule (1), a Government servant serving in a vacation department shall not be entitled to any earned leave in respect of duty performed in any year in which he avails himself of the full vacation.
- (3) (a) In respect of any year in which a Government servant avails himself of a portion of the vacation, he shall be entitled to earned leave in such proportion of 20 days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation.
- (b) If in any year, the Government servant does not avail himself of any vacation, earned leave shall be admissible to him in respect of that year under rule 25, earned leave, credited in advance in respect of that year in accordance with the provision of sub-rule (1) shall be adjusted against the earned leave so credited under rule 25.
- Explanation-** For the purpose of this rule, the term 'year' shall be construed not as meaning a calendar year in which duty is performed but as meaning twelve months of actual duty in a vacation department.

Note.- (1) A Government servant entitled to vacation shall be considered to have availed himself of a vacation or a portion of a vacation unless he has been required by general or special orders of a higher authority to forgo such vacation or portion of a vacation:

Provided that if he has been prevented by such order from enjoying more than fifteen days of the vacation, he shall be considered to have availed himself of no portion of the vacation.

Note.- (2) When a Government servant serving in a Vacation Department proceeds on leave before completing a full year of duty, the earned leave admissible to him shall be calculated not with reference to the vacations which fall during the period of actual duty rendered before proceeding on leave, but with reference to the vacation that falls during the year commencing from the date on which he completed the previous year of duty.

Note.- (3) In the case of a Government servant serving in a vacation department, the earned leave, if any, admissible under sub-rule (3) will be in addition to the earned leave admissible under sub-rule (1).

- (4) Vacation may be taken in combination with or in continuation of any kind of leave under these rules, provided that the total duration of the vacation and earned leave taken in conjunction, whether the earned leave is taken in combination with or in continuation of other leave or not, shall not exceed the amount of earned leave due and admissible to the Government servant at a time under rule 25.
- (5) The earned leave under this rule at the credit of a Government servant at the close of the previous half-year shall be carried forward to the next half-year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half-year do not exceed the maximum limit of 300 days.

Note- The facility of crediting of unavailed portion of joining time shall be admissible to persons serving in vacation department in accordance with the provision of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (1) of rule 25.

28. Half pay leave.- (1) The half pay leave account of every Government servant shall be credited with half pay leave in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.

- (2) (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of $5/3$ days for each completed calendar month of service, which he is likely to render in the half-year of the calendar year in which he is appointed.
- (b) The credit for the half-year in which a Government servant is due to retire or resigns from the service shall be allowed at the rate of $5/3$ days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation.
- (c) When a Government servant is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of half pay leave shall be allowed at the rate of $5/3$ days per calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.
- (d) Where a period of absence or suspension of a Government servant has been treated as 'dies-non' in a half-year, the credit to be accorded to his half pay leave account at the commencement of next half-year, shall be reduced by one eighteenth of the period of 'dies-non' subject to the maximum of ten days.

- (3) The leave under this rule may be granted to a Government servant on medical certificate or on private affairs. Such leave on medical certificate shall be given on production of a medical certificate from such medical authority as Government may by general or special order prescribe in this behalf and for a period not exceeding that recommended by the medical authority. Such medical leave shall not be granted unless the authority competent to sanction leave is satisfied that there is a reasonable probability that the Government servant will be fit to return to duty on its expiry. Half pay leave on private affairs also shall not be granted unless the authority competent to sanction leave has reasons to believe that the Government servant will return to duty on its expiry or unless it is included in the grant of leave expressed to be preparatory to retirement.
- (4) While affording credit of half pay leave, fraction of a day shall be rounded off to the nearest day.

29. Commuted leave.- (1) Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted on medical certificate only to a Government servant, subject to the following conditions:-

- (i) When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due.
- (ii) No commuted leave may be granted unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the Government servant will return to duty on its expiry.
- (iii) Commuted leave shall not be granted preparatory to retirement.
- (2) Half pay leave up to maximum of 180 days may be allowed to be commuted during entire service (without production of medical certificate) where such leave is utilized for an approved course of study certified to be in the public interest by the leave sanctioning authority.
- (3) Where a Government servant who has been granted commuted leave resigns from service or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave and the difference between the leave salary in respect of commuted leave and half pay leave shall be recovered :

Provided that no such recovery shall be made if the retirement is by reason of ill-health incapacitating the Government servant for further service or in the event of his death.

Note- Commuted leave may be granted at the request of the Government servant even when earned leave is due to him.

30. Leave not due.- (1) Save in the case of leave preparatory to retirement, leave not due may be granted to a Government servant, subject to the following conditions:-

(a) The authority competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the Government servant returning to duty on its expiry;

(b) Leave not due shall be limited to the half pay leave he is likely to earn thereafter;

(c) Leave not due during the entire service shall be limited to a maximum of 360 days, out of which not more than 90 days at a time and 180 days in all may be otherwise than on medical certificate;

(d) Leave not due shall be debited against the half pay leave, the Government servant may earn subsequently.

(2)(a) Where a Government servant who has been granted leave not due resigns from service or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty, the leave not due shall be cancelled, his resignation or retirement taking effect from the date on which such leave had commenced, and the leave salary shall be recovered.

(b) Where a Government servant who having availed himself of leave not due returns to duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently:

Provided that no leave salary shall be recovered under clause (a) or clause (b), if the retirement is by reason of ill-health incapacitating the Government servant for further service or in the event of his death:

Provided further that no leave salary shall be recovered under clause (a) or clause (b), if the Government servant is compulsorily retired prematurely under rule 42 (b) of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, or is retired under Fundamental Rule 56 (2)(a).

31. Extra-ordinary Leave.- (1) Subject to the provisions of rule 11, extra-ordinary leave may be granted to a Government servant in the following special circumstances:-

- (a) when no other kind of leave is admissible, or
 - (b) when any other kind of leave is admissible, but the Government servant applies in writing for the grant of extra-ordinary leave.
- (2) The authority competent to grant leave may retrospectively convert period of absence without leave into extra ordinary leave even when any other kind of leave was admissible at the time when absence without leave commenced
- (3) Extra-ordinary leave shall not be sanctioned to a Government servant during the period of notice given by him/her for seeking voluntary retirement.
- (4) Extra ordinary leave shall not be debited to the leave account.

32. Leave to probationer, a person on probation and an apprentice.-

(1)(a) A probationer shall be entitled to leave under these rules, if he had held his post substantively otherwise than on probation.

(b) If, for any reason, it is proposed to terminate the services of a probationer, any leave, which may be granted to him, shall not extend -

- (i) beyond the date on which the probationary period as already sanctioned or extended expires, or
- (ii) beyond any earlier date on which his services are terminated by the orders of an authority competent to appoint him.

(2) An apprentice shall be entitled to-

- (a) leave on medical certificate, on leave salary equivalent to half pay for a period not exceeding one month in any year of apprenticeship;
- (b) extra-ordinary leave under rule 31.

33. Leave preparatory to retirement.- (1) A Government servant may be permitted by the authority competent to grant leave to take leave preparatory to retirement to the extent of earned leave due, not exceeding 300 days together with half pay leave due, subject to the condition that such leave extends up to and includes the date of retirement.

Note- The leave granted as leave preparatory to retirement shall not include extra-ordinary leave.

- (2) Where a Government servant who is on foreign service in or under any local authority or a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Government or a body controlled or financed by the Government (hereinafter referred to as the local body) applies for leave preparatory to retirement the decision to grant or refuse such leave shall be taken by foreign employer with the concurrence of the lending authority under the State Government.
- (3) Where a Government servant is on Foreign Service in or under a local body other than the one mentioned in sub rule (2), leave preparatory to retirement shall be admissible to him only when he quits duty under the foreign employer.

34. Leave beyond the date of retirement, compulsory retirement or quitting of service.- No leave shall be granted to a Government servant beyond –

- (a) the date of his retirement, or
- (b) the date of his final cessation of duties, or
- (c) the date on which he retired by giving notice to Government or he is retired by Government by giving him notice or notice pay and allowances, in lieu of such notice, in accordance with the terms and conditions of his service, or
- (d) the date of his resignation from service.

35. Persons re-employed after retirement.- In the case of a person re-employed after retirement, the provision of these rules shall apply as if he had entered Government service for the first time on the date of his re-employment.

36. Leave Salary.- (1) A Government servant who proceeds on earned leave is entitled to leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on earned leave:

Provided that, if a Government servant on deputation to foreign service in India or officiating on a higher post, on reversion to his original post/cadre proceeds on earned leave without joining the post of his reversion, shall be entitled to draw leave salary equal to the pay which he would have drawn, but for his appointment to higher Post, immediately before proceeding on earned leave.

Note- In respect of any period spent on foreign service out of India, the pay which the Government servant would have drawn if on duty in India, but for foreign service out of India, shall be substituted for the pay actually drawn while calculating leave salary.

- (2) A Government servant on half pay leave or leave not due is entitled to leave salary equal to half the amount specified in sub-rule (1).
- (3) A Government servant on commuted leave is entitled to leave salary equal to the amount admissible under sub-rule (1).
- (4) A Government servant on extra-ordinary leave is not entitled to any leave salary.
- (5) In the case of a person to whom the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948) applies, leave salary payable during leave, other than earned leave, shall be reduced by the amount of benefit admissible under the said Act for the corresponding period.
- (6) (a) If, in the case of a Government servant who retires or resigns from service, the leave already availed of is more than the credit so due to him necessary adjustment shall be made in respect of leave salary, if any overdrawn.
(b) Where the quantum of earned leave already availed of by a Government servant who is dismissed or removed from service or who dies while in service is in excess of the leave credited under clause (b) of sub-rule (2) of rule 26, the over payment of leave salary shall be recovered in such cases.
- (7) A Government servant who is granted leave earned by him during the period of re-employment shall be entitled during such leave to leave salary as admissible under this rule, reduced by the amount of pension and pension equivalent of other retirement benefits.

37. Drawal of leave salary.- The leave salary payable under these rules shall be drawn in rupees in India

CHAPTER-V

SPECIAL KINDS OF LEAVE OTHER THAN STUDY LEAVE

- 38. Maternity leave.-** (1) Maternity leave may be granted to a female Government servant with less than two surviving children up to a period of 135 days from the date of its commencement. During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave.
- (2) Such leave shall not be debited against the leave account.
 - (3) Maternity leave may be combined with leave of any other kind.

- (4) Maternity leave may also be granted to a female Government servant (irrespective of the number of surviving children) in cases of miscarriage including abortion, subject to the condition that the leave shall be limited to the period recommended by the appropriate medical authority subject to a maximum of forty five days during the entire service.

Note- An abortion induced under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 shall also be considered a case of 'abortion' for the purpose of this rule, but however no leave shall be granted under this rule in cases of 'threatened abortion'. (AMENDMENT)

38-A. Paternity leave.- (1) A male Government servant with less than two surviving children may be granted paternity leave for a period of 15 days by an authority competent to grant leave during the confinement of his wife for child birth i.e., up to 15 days before or up to 6 months from the date of delivery of the child.

(2) During the period of such leave the Government servant shall be paid the leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) Paternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with any other kind of leave.

(4) If paternity leave is not availed of within the period specified in sub-rule (1), such leave shall be treated as lapsed.

Note- This leave shall not normally be refused.

38-B. Child Adoption Leave.- (1) A female Government servant with less than two surviving children may be granted Child Adoption Leave up to a period of 135 days (limited till the date the adopted child attains the age of 1 year) on legal adoption of a child up to one year of age. During such period, she will be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave.

(2) Child Adoption Leave may be combined with leave of any other kind.

(3) In continuation of 'Child Adoption Leave', the adoptive mother may also be granted, if applied for, the leave of the kind due and admissible (including leave not due and commuted leave not exceeding 60 (sixty) days without production of medical certificate) for a period up to one year reduced by the age of the adopted child on the date of legal adoption without taking into account the period of child Adoption Leave.

(4) Child Adoption Leave shall not be debited against the leave account.

- 39. Special disability leave for injury intentionally inflicted.-** (1) The authority competent to grant leave may grant special disability leave to a Government servant (whether permanent or temporary) who is disabled by injury intentionally inflicted or caused in, or in consequence of the due performance of his official duties or in consequence of his official position.
- (2) Such leave shall not be granted unless the disability manifested itself within three months of the occurrence to which it is attributed and the person disabled acted with due promptitude in bringing it to notice:
- Provided that the authority competent to grant leave may, if it is satisfied as to the cause of the disability, permit leave to be granted in cases where the disability manifested itself more than three months after the occurrence of its cause.
- (3) The period of leave granted shall be such as is certified by an Authorized Medical Attendant and shall in no case exceed 24 months.
- (4) Special disability leave may be combined with leave of any other kind.
- (5) Special disability leave may be granted more than once, if the disability is aggravated or reproduced in similar circumstances at a later date, but not more than 24 months of such leave shall be granted in consequence of any one disability.
- (6) Special disability leave shall be counted as duty in calculating service for pension and shall not be debited against the leave account.
- (7) Leave salary during such leave shall -
- (a) for the first 120 days of any period of such leave, including a period of such leave granted under sub-rule (5); be equal to leave salary while on earned leave; and
 - (b) for the remaining period of any such leave, be equal to leave salary during half pay leave.
- (8) In the case of a person to whom the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), applies, the amount of leave salary payable under this rule shall be reduced by the amount of benefit payable under the said Act for the corresponding period.

40. Special disability leave for accidental injury.- (1) The provisions of rule 39 shall apply also to a Government servant, whether permanent or temporary, who is disabled by injury accidentally incurred in, or in consequence of, the due performance of his official duties or in consequence of his official position or by illness incurred in the performance of any particular duty, which has the effect of increasing his liability to illness or injury beyond the ordinary risk attaching to the civil post which he holds.

(2) The grant of special disability leave in such case, shall be subject to the further conditions-

- (i) that the disability, if due to disease, must be certified by an Authorized Medical Attendant to be directly due to the performance of the particular duty;
- (ii) that, if the Government servant has contracted such disability during service otherwise than with a military force, it must be, in the opinion of the authority competent to sanction leave, exceptional in character; and
- (iii) that, the period of absence recommended by an Authorized Medical Attendant may be covered in part, by leave under this rule and in part by any other kind of leave, and that the amount of special disability leave granted on leave salary equal to that admissible on earned leave shall not exceed 120 days.

40-A. Power to grant special disability leave.- All cases relating to the grant of special disability leave under rules 39 and 40, shall be referred to the Administrative Department concerned for concurrence.

41. Power to grant leave other than special disability leave and study leave.- (1) The administrative department may designate leave sanctioning authorities for leave other than special disability leave and study leave in respect of Government servants serving in the department and may also prescribe the limits up to which and the conditions under which such authorities may sanction leave.

(2) All cases of leave other than those mentioned in sub-rule (1), shall be referred to the administrative department

Chapter VI

STUDY LEAVE

42. Conditions for grant of study leave.- (1) Subject to the conditions specified in these rules, study leave may be granted to a Government servant with due regard to the exigencies of public service to enable him to undergo, in or out of India, a special course of study consisting of higher studies or specialized training in a professional or a technical subject having a direct and close connection with the sphere of his duty.

(2) Study leave may also be granted -

- (i) for a course of training or study tour in which a Government servant may not attend a regular academic or semi-academic course, if the course of training or the study tour is certified to be of definite advantage to Government from the point of view of public interest and is related to the sphere of duties of the Government servant; and
- (ii) for the purpose of studies connected with the frame-work or back ground of public administration, subject to the conditions that -
 - (a) the particular study or study tour should be approved by the authority competent to sanction study leave; and
 - (b) the Government servant should be required to submit on his return, a full report of the work done by him while on study leave.
- (iii) for the studies which may not be closely or directly connected with the work of the Government servant, but which are capable of widening his mind in a manner likely to improve his abilities as a civil servant' and to equip him better to collaborate with those employed in other branches of the public service.

(3) Study leave shall not be granted unless-

- (i) it is certified by the Administrative Department that the proposed course of study or training shall be of definite advantage from the point of view of public interest;
- (ii) It is for prosecution of studies in subjects other than academic or literary subject:

Provided that a specialist or a technical person may be granted study leave, on merits of each case for prosecuting a postgraduate course of study directly related to the sphere of his duty in case the Secretary to the Department concerned certifies that the course of study shall enable the specialist or the technical person, as the case may be, to keep abreast with modern development in the field of his duty, improve his technical standards and competence and thus substantially benefit the Department.

(iii) The Economic Affairs Department of the Government of India, Ministry of Finance agree to the release of foreign exchange involved in the grant of study leave, if such leave is out of India.

(4) Study leave out of India shall not be granted for the prosecution of studies in subjects for which adequate facilities exist in India.

(5) Study leave may be granted to a regular Government servant -

(i) who has satisfactorily completed the period of probation and has rendered not less than five years' continuous service including the period of probation and service in ad-hoc capacity under the Government;

(ii) who is not due to reach the age of superannuation from the Government service within three years from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of leave;

(iii) who executes a bond as laid down in rule 49 undertaking to serve the Government for a period of three years after the expiry of leave.

(6) Study leave shall not be granted to Government servant with such frequency as to remove him from contact with his regular work or to cause cadre difficulties owing to his absence on leave.

43. Sanction of study leave.- (1) Study leave may be sanctioned to a Government servant by the Administrative Department.

(2) Where a Government servant borne permanently on the cadre of one department or establishment is serving temporarily in another department or establishment, the grant of study leave to him shall be subject to the condition that the concurrence of the department or establishment to which he is permanently attached is obtained before leave is granted.

(3) On completion of the course of study, the Government servant shall submit to the authority which granted him the study leave, the certificate of examination passed or special course of study undertaken, indicating the date of commencement and termination of the course with the remarks, if any, of the authority in charge of the course of study.

44. Maximum amount of study leave that may be granted at a time and during the entire service.- Maximum amount of study leave, which may be granted to a Government servant, shall be -

- (i) ordinarily twelve months at any one time which shall not be extended save for exceptional reasons; and
- (ii) during the entire service, twenty-four months in all (inclusive of similar kind of leave for study or training granted under any other rules).

45. Accounting of study leave and combination with leave of other kinds.- (1) Study leave shall not be debited against the leave salary of Government servant.

(2) Study leave may be combined with other kinds of leave, but in no case shall the grant of this leave in combination with leave other than extra-ordinary leave involve a total absence of more than twenty eight months generally and thirty-six month for the course leading to Ph.D. degree or a post graduate degree of more than twenty eight months duration from the regular duties of the Government servant.

(3) A Government servant granted study leave in combination with any other kind of leave may, if he so desires undertake or commence his study before the end of the other kind of leave but the period of such leave coinciding with the course of study shall not count as study leave.

Note- the limit of absence prescribed in sub-rule (2) includes the period of vacation.

46. Regulation of study leave extending beyond course of study.- When the course of study falls short of study leave sanctioned, the Government servant shall resume duty on the conclusion of the course of study, unless the previous assent of the authority competent to sanction leave to treat the period of short fall as ordinary leave has been obtained.

- 47. Admissibility of allowances in addition to leave salary.-** No allowance of any kind other than the dearness allowance shall be admissible to a Government servant in respect of the period of study leave granted to him.
- 48. Grant of travelling allowance.-** A Government servant shall not ordinarily be paid travelling allowance, but the Governor may in exceptional circumstances sanction the payment of such allowance.
- 49. Execution of bond.-** Every Government servant in permanent employ who has been granted study leave or extension of such leave shall be required to execute a bond as given in Form 5 or Form 6, as the case may be, before the study leave or extension of such leave granted to him commences. If study leave or extension of such leave is granted to a Government servant not in permanent employ, the bond shall be executed as given in Form 7 or Form 8 as the case may be.
- 50. Resignation or retirement after study leave or non-completion of course of study.-** (1) If a Government servant resigns or retires from service or otherwise quits service without returning to duty after a period of study leave or within a period of three years after such return to duty or fails to complete the course of study and is thus unable to furnish the certificate as required under sub-rule (3) of rule 43 he shall be required to return -
- (i) the actual amount of leave salary, cost of fees, travelling and other expenses, if any, incurred by the Government; and
 - (ii) the actual amount if any, of the cost incurred by other agencies such as foreign Governments, Foundations and Trusts in connection with the course of study, together with an annual rate of 12% interest thereon from the date of demand, before his resignation is accepted or permission to retire is granted or his quitting service otherwise:
Provided that except in the case of employees who fail to complete the course of study nothing in this rule shall apply -
 - (a) a Government servant who on return to duty from study leave is permitted to retire from service on medical grounds; or

- (b) to a Government servant who on return to duty from study leave is deputed to serve in any autonomous body or in any institution under the control of the Government, and is subsequently permitted to resign from the service under the Government with a view to his permanent absorption in the said statutory or autonomous body or institution in the public interest.
- (2) (a) The study leave availed of by such a Government servant shall be converted into regular leave standing at his credit on the date on which the study leave commenced, any regular leave taken in continuation of study leave being suitably adjusted for the purpose and the balance of the period of study leave, if any, which cannot be so converted, treated as extra-ordinary leave.
- (b) In addition to the amount to be refunded by the Government servant under sub-rule (1), he shall be required to refund any excess of leave salary actually drawn over the leave salary admissible on conversion of the study leave.
- (3) Notwithstanding anything contained in this rule, the Governor may, if it is necessary or expedient to do so, either in public interest or having regard to the peculiar circumstances of the case or class of cases, by order, waive or reduce the amount required to be refunded under sub-rule (1) by the Government servant concerned or class of Government servants.

51. Leave salary during the study leave.- (1) During study leave availed, a Government servant shall draw leave salary equal to the pay (without allowance other than dearness allowance) that the Government servant drew while on duty with Government immediately before proceeding on such leave.

- (2) (a) Payment of leave salary on full rate under clause (a), shall be subject to furnishing of a certificate by the Government servant to the effect that he is not in receipt of any scholarship, stipend or remuneration in respect of any part time employment.
- (b) The amount, if any, received by a Government servant during the period of study leave as scholarship or stipend or remuneration in respect of any part- time employment, shall be adjusted against the leave salary payable under this sub-rule, subject to the condition that the leave salary shall not be reduced to an amount less than that payable as leave salary during half pay leave.

52. Counting of study leave for promotion, pension, seniority, leave and increments.- Study leave shall count as service for promotion, pension and seniority. It shall also count as service for increments as provided in rule 26 of the Fundamental Rules.

53. Application for study leave.- (1)(a) Every application for study leave shall be submitted through proper channel to the authority competent to grant leave.

(b) The course or courses of study contemplated by the Government servant and any examination, which he proposes to undergo, shall be clearly specified in such application.

(2) Where it is not possible for the Government servant to give full details in his application, or if, after leaving India he is to make any change in the programme which has been approved in India, he shall submit the particulars as soon as possible to the Head of the Mission or the authority competent to grant leave, as the case may be and shall not, unless prepared to do so at his own risk, commence the course of study or incur any expenses in connection therewith until he receives the approval of the authority competent to grant the study leave for the course.

CHAPTER-VII **MISCELLANEOUS**

54. Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Finance Department for decision.

55. Repeal and saving.- (1) On the commencement of these rules, every rule, regulation or order, including memorandum (hereinafter referred to in this rule as the old rule) in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate.

(2) Notwithstanding such cesser of operation, anything done or any action taken or any leave earned by, or granted to, or accrued to the credit of a Government servant, under the old rule, shall be deemed to have been done, taken, earned, granted or accrued under the corresponding provisions of these rules.

(3) For the purposes of grant of leave under these rules, the powers delegated under the old rules shall continue to apply.

FORM 1
(See Rule 13)

APPLICATION FOR LEAVE OR FOR EXTENSION OF LEAVE

1. Name of applicant
2. Leave Rules applicable
3. Post held
4. Office and Section
5. Pay
6. House rent allowance, conveyance allowance or other *compensatory allowances drawn in the present post.
7. Nature and period of leave applied for and date from which required.
8. Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/suffixed to leave.
9. Ground on which leave is applied for
10. Date of return from last leave, and the nature and period of that leave
11. Leave address, if granted
12. I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession for the block years during the ensuing leave

Signature of Applicant (with date)
Designation

13. Remarks and/or recommendation of the Controlling! Officer

Signature (with date)
Designation

14. Orders of the sanctioning authority

Signature (with date)
Designation

***If the applicant is drawing any compensatory allowance the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.**

(On Private Affairs and MC Including commuted leave and leave not due)

TAKEN						LND Limited to 360 days in entire service										
Commuted leave on medical certificate on full pay			Commuted leave W/O M.C. for studies certificate to be in public interest limited to 180 days (H.P.L. converted into 90 days commuted leave in entire service			Commuted leave converted into half pay leave (Twice of Cols. 2&25)	On medical certificate			Otherwise than on M.C.			Total of leave not due (Col. 29+32)	Total half pay leave taken (Col. 19+26+33)	Balance of half pay leave on return from leave (Col. 16-34)	Other kinds of leave taken
From	To	No. of days	From	To	No. of days		From	To	No. of days	From	To	No. of days				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

- Note 1.** The Earned Leave due should be expressed in days.
- Note 2.** When a Government servant is appointed during the course of a half-year of a particular calendar year, earned leave should be credited at the rate of 2-1/2 days for each completed calendar month and the fraction of a day will be rounded to the nearest day.
- Note 3.** Period of extraordinary leave should be noted in red ink

FORM 3
(See Rule 17)
MEDICAL CERTIFICATE FOR GOVERNMENT SERVANTS
RECOMMENDED LEAVE OR EXTENSION OF
LEAVE OR COMMUTATION OF LEAVE

Signature of the Government servant

I, after careful personal examination of the case hereby certify that Shri/Shrimati/Kumariwhose signature is given above, is suffering from and I consider that a period of absence from duty ofwith effect from.....is absolutely necessary for the restoration of his/her health.

Authorized Medical Attendant,
.....Hospital/Dispensary or
other Registered Medical Practitioner .

Dated

Note (1). - The nature and probable duration of the illness should be specified.

Note (2). - This Form should be adhered to as closely as possible and should be filled in after the signature of the Government servant has been taken. The certifying officer is not at liberty to certify that the Government servant requires a change from or to a particular locality, or that he is not fit to proceed to a particular locality. Such certificates should only be given at the explicit desire of the administrative authority concerned, to whom it is open to decide, when an application on such grounds has been made to him, whether the applicant should go before a Civil Surgeon or Staff Surgeon to decide the question of his/her fitness for service.

Note (3). - Should a second medical opinion be required, the authority competent to grant leave should arrange for the second medical examination to be made at the earliest possible date by a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon or Staff Surgeon who shall express an opinion both as regards the facts *of* the illness and as regards the necessity for the amount of leave recommended and for this purpose he may either require the Government servant to appear before himself or before a medical officer nominated by himself.

Note (4). - No recommendation contained in this certificate shall be evidence of a claim to any leave not admissible to the Government servant.

FORM 4
[See Rule 23 (3)]

MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS TO RETURN TO DUTY

Signature of the Government servant

I,Civil Surgeon/Staff Surgeon, Authorized
Medical Attendant, Registered Medical Practitioner of
.....Do hereby certify that I have carefully examined
Shri/Shrimati/Kumariwhose signature is
given above, and find that he/she has recovered from his/her illness and is
now fit to resume duties in Government service. I also certify that before
arriving at this decision, I have examined the original medical certificate (s)
and statement (s) of the case (or certified copies thereof) on which leave
was granted or extended and have taken these into consideration in arriving
at my decision.

Civil Surgeon/Staff Surgeon,
Authorized Medical Attendant,
Registered Medical Practitioner .

Dated

Note.- The original medical certificate (s) and statement (s) of the case on
which the leave was originally granted or extended shall be produced before
the authority required to issue the above certificate. For this purpose, the
original certificate (s) and statement (s) of the case should be prepared in
duplicate, one copy being retained by the Government servant concerned.

FORM 5
(See Rule 49)

**BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT IN
PERMANENT EMPLOY WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE**

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I,
..... resident of in the District of
.....at present employed as in the Department/office
of do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay
to the Governor of Chhattisgarh (hereinafter called the "Government") on
demand the sum of Rs. Rs.....only)
together with interest thereon from the date of demand at an annual rate of
12%, or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of
the said amount in the currency of that country converted at the official rate
of exchange between that country and India AND TOGETHER With all
costs between attorney and client and all charges, and expenses that shall or
may have been incurred by the Government.

WHEREAS I,am granted study leave
by Government.

AND WHEREAS for the better protection of the Government I have
agreed to execute this bond with such conditions as hereunder is written.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN
OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or
resigning or retiring from service or otherwise quitting service, Without
returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave
or at any time Within a period of three years after my return to duty I shall
forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government
on demand the said sum of Rs. (Rupees only)
together with interest thereon at an annual rate of 12%. In the case of the
breach of the conditions of this bond, the amount mentioned above shall be
recovered as arrears of Land revenue.

AND upon my making such payment the above written obligation
shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force
and virtue.

The Government of Chhattisgarh have agreed to bear the stamp duty payable
on this bond

Signed and dated this. day of two thousand and
..... **Signature** **Accepted**

Signed and delivered by **For and on behalf of the**
in the presence of **Governor of Chhattisgarh**

Witness: (1).

Witness: (2).

FORM 6
(See Rule 49)

**BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT
IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY
LEAVE**

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, resident ofin the District of at present employed as in the department/Office of do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay the Governor of Chhattisgarh (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs (Rupees) Together With interest thereon from the date of demand at an annual rate of 12% or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs Lo between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS I,was granted study leave by Government for the period from to in consideration of which I executed a bond, dated , for Rs..... (Rupees only) in favour of the Governor of Chhattisgarh.

AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to me at my request until

AND WHEREAS for the better protection of the Government I have agreed to execute this bond with such condition as hereunder is written.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or resigning or retiring from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave so extended or failing to complete the course of study or any time within a period of three years after my return to duty, I shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government on demand the said sum of Rs..... (Rupees.....only) together with interest thereon at an annual rate of 12%. In the case of the breach of the conditions of this bond, the amount mentioned above shall be recovered as arrears of Land revenue.

AND upon my making such payment the above written obligation shall be void and of no effect otherwise it shall be and remain in full force and virtue.

The Government of Chhattisgarh have agreed to bear the stamp duty payable on this bond.

Signed and dated this.....day of two thousand and.....

Signed and delivered by
in the presence of

Witness -(1)

Witness- (2)

ACCEPTED
For and on behalf of the Governor
of Chhattisgarh.

**FORM 7
(See Rule 49)**

**BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT
IN PERMANENT EMPLOY: WHEN PROCEEDING ON STUDY
LEAVE**

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE resident of in the District of at present employed asin the Department/Office of("hereinafter called the obligor") and Shri/ Shrimati/ Kumari..... son/daughter of..... (hereinafter called the "sureties") do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators to pay to the Governor of chhattisgarh (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs(Rupeesonly) together with interest thereon at an annual rate of 12%, or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS the obligor is granted study leave by the Government: AND WHEREAS for the better protection of the Government the obligor has agreed to execute this bond with such condition as hereunder is written:

AND WHEREAS the said sureties have agreed to execute this bond as sureties on behalf of the above bounden NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of the obligor Shri/Smt./Kumari..... failing to resume duty, or resigning from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave or at any time within a period of three years after his return to duty the obligor and the sureties shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government on demand the said sum of Rs (Rs. only) together with interest thereon at an annual rate of 12%. In the case of the breach of the conditions of this bond, the amount mentioned above shall be recovered as arrears of Land revenue.

And upon the obligor Shri/Shrimati/kumari and/or Shri/Shrimati/Kumarithe sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall be void and of no effect otherwise it shall be and remain in full force and virtue:

PROVIDED ALWAYS that the liability of the sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by them (whether with or without the consent or knowledge of the sureties) nor shall it be necessary, for the Government to sue the obligor before suing the sureties Shri/Shrimati/kumari and Shri/Shrimati/kumari..... or any of them for amounts due hereunder .

The Government of Chhattisgarh have agreed to bear the stamp duty payable on this bond.

Signed and dated thisday oftwo thousand and

Signed and delivered by the obligor above named Shri/Shrimati/Kumari

.....
in the presence of

Witness: (1)
(2)

Signed and delivered by the surety above named Shri/Shrimati/kumari

.....
in the presence of

Witness: (1)
(2)

Signed and delivered by the surety above named Shri/Shrimati/kumari

.....
in the presence of

Witness: (1)
(2)

ACCEPTED
For and on behalf of the
Governor of Chhattisgarh

FORM 8
(See Rule 49)

**BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT IN
PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE**

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT we, residents ofin the District ofat present employed as in the Department/Office of (hereinafter called "the obligor") and Shri/Shrimati/Kumari..... son/daughter of..... and Shri/Shrimati/Kumari..... son/daughter of(hereinafter called "the sureties") do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators to pay to the Governor of Chhattisgarh (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs(Rupees) together with interest thereon from the date of demand at an annual rate of 12% or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS the obligor was granted study leave by the Government for the period fromto in consideration of which he executed a bond datedfor Rs (Rs) in favour of the Governor of Chhattisgarh.

AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to the obligor at his request until: AND WHEREAS for the better protection of the Government the obligor has agreed to execute this bond with such condition as hereunder is written. AND WHEREAS the said sureties have agreed to execute this bond as sureties on behalf of the above bounden

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of the obligor Shri/Shrimati/Kumari..... failing to resume duty, or resigning from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave so extended or at any time within a period of three years after his return to duty, the obligor and the sureties shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs {Rupees) together with interest thereon from the date of demand at an annual rate of 12%. In the case of the breach of the conditions of this bond, the amount mentioned above shall be recovered as arrears of Land revenue.

AND upon the obligor Shri/Shrimati/Kumari

.....and/or Shri/ Shrimati/
Kumari.....and/or Shri/Shrimati/Kumari
.....the sureties aforesaid making such payment
the above written obligation shall be void and of no effect otherwise it shall
be and remain in full force and virtue :

PROVIDED ALWAYS that the liability of the sureties hereunder shall not
be impaired or discharged by reason of time being granted or by any
forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by
them (whether with or without the consent or knowledge of the sureties) nor
shall it be necessary for the Government to sue the obligor before suing the
sureties Shri/Shrimati/Kumariand Shri/
Shrimati/Kumari or any of them for amounts
due hereunder.

The Government of Chhattisgarh have agreed to bear the stamp duty,
payable on this bond.

Signed and delivered by the obligor
above named Shri/Shrimati/Kumari

.....
in the presence of

Witness: (1)
(2)

Signed and delivered by the surety
above named Shri/Shrimati/kumari
.....
in the presence of

Witness: (1)
(2)

Signed and delivered by the surety
above named Shri/Shrimati/kumari
.....
in the presence of

Witness: (1)
(2)

ACCEPTED
For and on behalf of the
Governor of Chhattisgarh

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

E.mail Id- dharsiwacollege1989@gmail.com Web site- www. gpscsc.in contact No. 9893119114

क्रमांक/1012/स्था./अवकाश/2021- 22

रायपुर, दिनांक 04.10.22

आदेश

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय के आदेश क्र. 492/एफ 2014-7/-00/83/वित्त/नियम/चार अटल नगर दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के परिपेक्ष्य में डॉ. श्रीमती सुनीता दुबे, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य को 59 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पद	स्वीकृत अवकाश का स्वरूप	स्वीकृत अवकाश दिवस /तिथि
01	डॉ. श्रीमती सुनीता दुबे,	सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)	संतान पालन अवकाश	03.03.2022 से 30.04.2022 तक कुल दिवस 59 दिन

(डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्दिकी)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय

धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

पृ. / क्रमांक/ /स्था./अवकाश/2021- 22

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1 संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)
- 2 स्थापना विभाग शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)
- 3 संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

(डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्दिकी)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय

धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

E.mail Id- dharsiwecollege1989@gmail.com Web site- www.gpscsc.in contact No. 9893119114

क्रमांक / 205 / स्था. / अवकाश / 2022-23

रायपुर, दिनांक 07/10/2022

आदेश

उत्तीसगठ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय के आदेश क्र. 492/एफ 2014-7/-CO/83/वित्त/नियम/चार अटल नगर दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के परिपेक्ष्य में डॉ. रश्मि कुजूर सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र को 23 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद	स्वीकृत अवकाश का स्वरूप	स्वीकृत अवकाश दिवस / तिथि
01	डॉ. रश्मि कुजूर	सहायक प्राध्यापक - समाज शास्त्र	संतान पालन अवकाश	08.09.2022 से 30.09.2022 तक कुल दिवस 23 दिन

(डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्दिकी)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

पृ. / क्रमांक / 206 / स्था. / अवकाश / 2022-2023

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1 संबंधित अधिकारी / कर्मचारी शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)

2 स्थापना दिनांक शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)

3 संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

(डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्दिकी)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

E.mail Id- dharsiwacollege1989@gmail.com Web site- www. gpscsc.in contact No. 9893119114

कमांक / 907 / स्था. / अवकाश / 2021- 22

रायपुर, दिनांक 22/03/2022

आदेश

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय के आदेश क्र. 492/एफ 2014-7/-00/83/वित्त/नियम/चार अटल नगर दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के परिपेक्ष्य में डॉ. श्रीमती जी. नाग भार्गवी सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र को 29 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद	स्वीकृत अवकाश का स्वरूप	स्वीकृत अवकाश दिवस / तिथि
01	डॉ. श्रीमती जी. नाग भार्गवी	सहायक प्राध्यापक - भौतिक शास्त्र	संतान पालन अवकाश	10.02.2022 से 10.03.2022 तक कुल दिवस 29 दिन

(डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्दिकी)
प्रभारी प्राचार्य

शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. / कमांक / / स्था. / अवकाश / 2021- 22
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक

- 1 संबंधित अधिकारी / कर्मचारी शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)
- 2 स्थापना विभाग शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)
- 3 संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

(डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्दिकी)
प्रभारी प्राचार्य

शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

E.mail Id- dharsiwacollege1989@gmail.com Web site- www. epscsc.in contact No. 9893119114

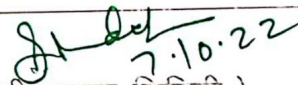
क्रमांक / 207 /स्था./अवकाश/2022- 23

रायपुर, दिनांक 07/10/2022

आदेश

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय के आदेश क्र. 492/एफ 2014-7/-00/83/वित्त/नियम/चार अटल नगर दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के परिपेक्ष्य में डॉ. श्रीमती जी. नाग भार्गवी सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र को 06 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पद	स्वीकृत अवकाश का स्वरूप	स्वीकृत अवकाश दिवस /तिथि
01	डॉ. श्रीमती जी. नाग भार्गवी	सहायक प्राध्यापक - भौतिक शास्त्र	संतान पालन अवकाश	19.09.2022 से 24.09.2022 तक कुल दिवस 06 दिन


(डॉ. श्रीमती शुकल सिद्धिकी)
प्रभारी प्राचार्य


शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा (शंकरनगर) रायपुर (छ.ग.)

पृ. / क्रमांक / 208 /स्था./अवकाश/2022-2023

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1 संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)
- 2 स्थापना विभाग शासकीय महाविद्यालय, शंकरनगर (धरसीवा), रायपुर (छ.ग.)
- 3 संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


(डॉ. श्रीमती शुकल सिद्धिकी)
प्रभारी प्राचार्य

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा (शंकर नगर) रायपुर (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा, रायपुर (छ.ग.)

E.mail Id- dharsiwacollege1989@gmail.com Web site- www. gpssc.in contact No. 9893119114

क्रमांक / 110 / / 2022

धरसीवा, दिनांक 20.08/2022

- // अनुमति आदेश // -

UGC- Human Resource Development Centre, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा 22.8.2022 से 05.09.2022 तक गणित विषय में Online Refresher Course आयोजित किया जा रहा है जिसमें महाविद्यालय के डॉ. निधि देवांगन, सहायक प्राध्यापक (गणित) को शामिल होने की अनुमति दी जाती है। एवं Refresher Course के लिए दिनांक 20.08.2022 अपरान्ह से कार्यमुक्त किया जाता है।

(डॉ. श्रीमती शबनूर सिद्दिकी)
प्रभारी प्राचार्य

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय
धरसीवा (रायपुर) (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 340/322/वि/नि/चार/03
प्रति,

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2003

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985-अंशदान और अनुरूपी बीमा राशि की दरों में 01 जुलाई 2003 से वृद्धि ।

विषयांतर्गत योजना की वर्तमान दरें दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू है । उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था । विभिन्न कर्मचारी संघों से विचारोपरांत शासन ने उक्त दरों में दिनांक 01 जुलाई, 2003 से 50 प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर रूपये 30 करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 जुलाई, 2003 (जून 2003 का वेतन जुलाई 2003 में देय) से निम्नानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की जाती है:-

समूह	कर्मचारी वर्ग	अभिदान प्रतिमाह	बीमा राशि
ए	प्रथम	रू. 240	रू. 2,40,000
बी	द्वितीय	रू. 180	रू. 1,80,000
सी	तृतीय	रू. 150	रू. 1,50,000
डी	चतुर्थ	रू. 90	रू. 90,000

2/ पूर्व की भांति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा । सेवानिवृत्त होने पर शासकीय सवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जायेगा । सेवा में

रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके अलावा इस योजना के तहत बचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी ब्याज सहित किया जायेगा ।

3/ दिनांक 1.7.2003 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की बढ़े हुए दरें उन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य होगी जो वर्तमान में समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य हैं, ऐसे शासकीय सेवकों को अभिदान की बढ़ी हुई दरें स्वीकार करने अथवा न करने का विकल्प की पात्रता नहीं होगी । ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अभिदान की संशोधित दरों के अधिसूचित किये जाने के बाद सेवा में आते हैं वे भी अनिवार्य रूप से 1 जुलाई, 2003 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की संशोधित दरों के साथ ही योजना में सम्मिलित होंगे । इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों को शासकीय सेवा का कार्यभार संभालने की तारीख से 30 जून, 2003 तक वर्तमान में प्रभावशील दरों के अंतर्गत बीमा रक्षण राशि का लाभ दिया जायेगा ।

4/ छत्तीसगढ़ शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 के सदस्य दिनांक 1 जुलाई, 2003 से वह योजना छोड़कर छत्तीसगढ़ कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 की संशोधित दरों के अनुसार सदस्यता ले सकते हैं । इसके लिये उन्हें दिनांक 15 जून, 2003 तक संलग्न प्रपत्र में विकल्प अनिवार्यतः देना होगा । विकल्प के लिये निर्धारित तारीख को बढ़ाया नहीं जायेगा । एक बार दिया गया विकल्प अंतिम समझा जायेगा और आगे विकल्प देने का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा ।

5/ उपरोक्त पैरा-4 के अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 से इस योजना में विकल्प देने वाले कर्मचारियों से नियमानुसार विकल्प प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख द्वारा इस पर प्रतिहस्ताक्षर करते हुए इसकी प्रविष्टि संबंधित के सेवा पुस्तिका में भी अनिवार्य रूप से की जावेगी । ऐसे कर्मचारियों की नामवार सूची तैयार कर अनिवार्य रूप से दिनांक 30.6.2003 तक आयुक्त, कोष एवं लेखा (जीवन बीमा प्रकोष्ठ) छत्तीसगढ़, रायपुर को भेजी जावे ।

6/ राज्य शासन की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 के सदस्य न होते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य हैं ।

सहपत्र:- विकल्प का नमूना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

विकल्प

प्रति,

(कार्यालय प्रमुख)

महोदय/महोदया,

मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 का सदस्य हूँ । मैं दिनांक 1 जुलाई, 2003 (माह जून, 2003 का वेतन जुलाई, 2003 में देय) से वृद्धि किये गये अंशदान की राशि और अनुरूपी बीमारक्षण राशि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ समूह बीमा योजना, 1985 का सदस्यता ग्रहण करना चाहता/चाहती हूँ । मैंने उक्त योजना में निहित निर्देशों को मूल योजना के संदर्भ में पढ़ और समझ लिया है।

भवदीय/भवदीया

स्थान:

दिनांक:

(शासकीय सेवक का नाम, पदनाम)

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
 3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
 4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
 5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
 7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
 8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
 10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
 11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
 12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
 13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
 14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
 18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 19. नियंत्रक, शासकीय लेखा सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग